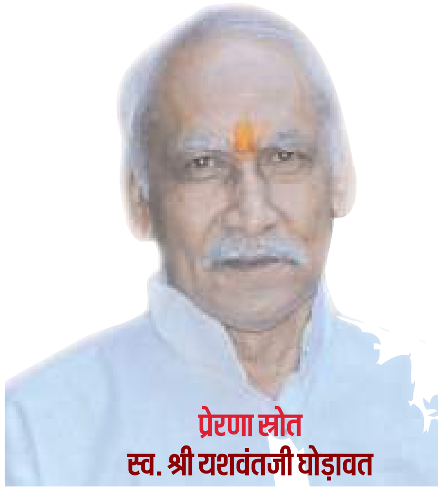

प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ..सच

# माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

**सुविचार**

मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है।
स्वामी विवेकानंद

वर्ष-03, अंक - 48 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 02 सितम्बर 2021 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

## पीएम मोदी ने जारी किया 125 रुपए का स्मारक सिक्का

**नई दिल्ली, एजेन्सी।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के मौके पर ऑनलाइन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उनकी स्मृति में 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि, इस्कॉन ने दुनिया भर को बताया कि, आस्था का मतलब होता है - उमंग, उत्साह और मानवता पर विश्वास। हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं, और वहां जब लोग 'हरे कृष्ण' बोलकर मिलते हैं तो हमें कितना अपनापन लगता है, कितना गौरव भी होता है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि, सुखद संयोग है कि, ऐसे महान देशभक्त का 125वां जन्मदिन ऐसे समय में हो रहा है, जब देश अपनी आजादी के 75 साल का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकि कृष्णभक्त थे, साथ ही वो महान भारत भक्त भी थे।

# भारत ने पहली बार की तालिबान से बातचीत

**नई दिल्ली, एजेन्सी।**

तालिबान के भारत की तरफ वार्ता का कदम बढ़ाने और वार्ता की पेशकश के बाद आखिरकार भारत ने भी बातचीत शुरू कर दी है। दोनों के बीच दोहा में पहली बार बातचीत हुई है। ये बातचीत भारत ने अपनी शर्तों पर की है। इस भारत ने दोटूक अपनी बात तालिबान की राजनीतिक शाखा के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई के समक्ष रखी हैं। इस बातचीत के कई मायने हैं। दोनों के बीच हुई इस बातचीत के तीन मुख्य बिंदु थे। इनमें पहला था आने वाले दिनों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी, दूसरा,उन अफगान नागरिकों को जो वहां से निकलना चाहते हैं बिना रोकटोक जाने देने की इजाजत और तीसरा था अफगानिस्तान की भूमि को भारत के खिलाफ इस्तेमाल न होने देना। इन सभी पर फिलहाल स्तानिकजई ने अपनी सहमति भी जता दी है।

इससे पहले भी एक बार ये अफवाह उड़ी थी कि, भारत ने दोहा में तालिबान के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की थी। हालांकि सरकार द्वारा इसका खंडन कर दिया गया था। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। वर्तमान में हुई बातचीत की जानकारी सरकार ने ही सार्वजनिक की है। ये बातचीत इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि तालिबान पहले से ही अफगानिस्तान में भारत सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की तारीफ करता रहा है। तालिबान की पूरी कोशिश है कि भारत किसी भी तरह से उससे बातचीत करे और उसका सहयोग करे। तालिबान ने पहले ही ये साफकर दिया था कि वो भारत द्वारा चलाए जा रहे विकासकार्यों को जारी रखना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि भारत बिना रोकटोक ये जारी रखे।

गौरतलब है कि भारत ने तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद 16-31 अगस्त के बीच वहां पर रहे करीब 800 लोगों को बाहर निकाला है। इनमें भारतीय नागरिकों के अलावा वहां पर रह रहे सिख और हिंदू शामिल थे। वर्तमान में भारत और तालिबान के बीच जो बातचीत हुई है यदि वो आगे भी जारी रहती है और कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं तो इसके काफी दूरगामी परिणाम भी सामने आ सकते हैं।

## ओवैसी की रैली में उड़ी कोविड-19 के नियमों की धज्जियां, 303 नेताओं पर केस दर्ज

**नई दिल्ली।** एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में कोविड-19 के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ीं। 3 सितंबर को होने वाले निगम चुनाव को लेकर ओवैसी ने कर्नाटक के बेलगावी में रैली की। बेलगावी यात्रा के दौरान प्रचारकों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक थी जिसके बाद पुलिस ने एआईएमआईएम के 303 नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफकोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया।

साथ ही कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ओवैसी कर्नाटक में होने वाले निगम चुनावों से पहले अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए एक प्रचार रैली के लिए बेलगावी गए थे। एआईएमआईएम ने 6 उम्मीदवार उतारे हैं। बेलगावी में 58 वार्डों के लिए नगर निगम के चुनाव 3 सितंबर को होने हैं और वोटों की गिनती 6 सितंबर को होगी।

## ज्योतिरादित्य सिंधिया की हरी झंडी से इंदौर-दुबई उड़ान 17 माह बाद फिर हुई शुरू

**इंदौर।** देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार काबू में हैं। ऐसे में ऑफिस, कालेज, स्कूल, माल आदि सेवाएं शुरू हो रही हैं। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया की इंदौर-दुबई उड़ान करीब 17 महीने के लम्बे अंतराल के बाद बुधवार को शुरू हो गई। मध्यप्रदेश की इस इकलौती अंतरराष्ट्रीय उड़ान का परिचालन कोविड-19 के प्रकोप के कारण मार्च 2020 में रोक दिया गया था, जिसे महामारी की स्थिति नियंत्रण में आने के बाद दोबारा शुरू किया गया है।

देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कांफ्रेस से हिस्सा लिया और इस उड़ान को हरी झंडी दिखाई। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सिंधिया ने इस मौके पर कहा, 'इंदौर-दुबई उड़ान 17 महीने बाद बहाल की जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि, एयर इंडिया का विमान हर बुधवार को भारतीय मानक समय के मुताबिक, इंदौर से दोपहर 12 बजकर 35 मीनिट पर उड़ान भरकर दोपहर 3 बजकर 5 मीनिट पर दुबई पहुंचेगा। वापसी में यह विमान दुबई से हर बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात के मानक समय के मुताबिक, शाम 4 बजकर 5 मीनिट पर रवाना होकर रात 8 बजकर 55 मीनिट पर इंदौर आएगा। जानकारों का कहना है कि, इस उड़ान के बहाल होने से मध्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पर्यटन तथा कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यात्रियों की बरसों पुरानी मांग के आधार पर इंदौर-दुबई उड़ान 15 जुलाई 2019 को शुरू हुई थी।

## केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने की स्कूल खुलने पर राज्यों की समीक्षा

**नई दिल्ली।** कोविड-19 के प्रकोप के कम होने के साथ ही देश के कई राज्यों में बुधवार से उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल पुनः खोल दिए गए हैं।

इसी के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय एवं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश भर में फिर से खुलने वाले स्कूलों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सितंबर तक स्कूलों में सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफका टीकाकरण करने के रोडमैप का भी जायजा लिया।

शिक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि, भारत सरकार स्कूलों को फिर से खोलने के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए देश भर के स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के टीकाकरण को प्राथमिकता दे रही है।

उधर, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी सभी राज्य सरकारों को कोरोना वैक्सीन की अतिरिक्त खेप भेजने के वादे के साथ ही 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस से पहले तक देश भर के सभी स्कूल शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने को कहा है। वहीं इस बीच, बुधवार से मध्यप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों ने उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं के लिए फिर से स्कूल खोल दिए गए हैं।

## ईडी के सामने पेश होने से ममता की बहू ने किया इंकार

**नई दिल्ली, एजेंसी।** पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह दिल्ली नहीं आ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय को जो भी पूछताछ करनी है वह कोलकाता स्थित उनके आवास पर ही की जाए। रुजिरा बनर्जी ने कहा है कि उनके दो छोटे बच्चे हैं, जिनके साथ कोरोना के समय में दिल्ली का सफर करना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए, उनसे कोलकाता में ही पूछताछ की जाए।

**रुजिरा व अभिषेक बनर्जी, दोनों को ईडी ने भेजा था समन**

बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को ईडी की ओर से कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के कथित आरोपों को लेकर समन जारी किया गया था। रुजिरा बनर्जी को बुधवार यानी आज दिल्ली स्थिति ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होना था। जबकि, अभिषेक बनर्जी को 6 सितंबर को पूछताछ के लिए पेश होना है। अभिषेक बनर्जी लोकसभा में डायमंड हार्बर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं।

## भ्रष्टाचार मामले में दो सरकारी कर्मचारियों को 4 वर्ष की कैद

**ग्वालियर।** मध्यप्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी मर्यादित के दो अधिकारियों क्षेत्रीय प्रबंधक राजेंद्र कुमार गुप्ता एवं केंद्रीय गोदाम प्रभारी राजेश गुप्ता को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर विशेष सत्र न्यायालय ने 4-4 साल जेल में कैद की सजा सुनाई है। एमपी ईओडब्ल्यू ने इस मामले की जांच की थी। सन् 2012 में स्पेशल कोर्ट में यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया था।

ईओडब्ल्यू की जिला अभियोजन अधिकारी राखी सिंह ने बताया कि, मध्यप्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित ग्वालियर के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेंद्र कुमार गुप्ता व सह अभियुक्त राजेश गुप्ता सहित एक अन्य आरोपित ने 26 लाख रुपए का गबन किया था। इस मामले की शिकायत पर आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने मामले की जांच की, जिसमें पाया गया कि आरोपितों ने 26 लाख रुपए निकालकर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर भ्रष्टाचार किया है। आरोपितों के खिलाफमामला दर्ज किया गया। ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया।

## जर्जर हो चुके स्कूल का पीएमओ ने लिया संज्ञान

**डिंडौरी।** मध्यप्रदेश में जर्जर हो रहे स्कूलों पर अब सख्ती बरती जा रही है, डिंडौरी जिले के शहपुरा तहसील मुख्यालय में जर्जर हो चुके कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारीयों को तलब करते हुए मामले की जानकारी मांगी है, जिसके बाद जिले के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया।

दरअसल, डिंडौरी जिले के शहपुरा तहसील मुख्यालय में संचालित कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है, भवन की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है की वो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है। हैरत की बात तो यह है की लोकनिर्माण विभाग के अधिकारी ने स्कूल भवन का निरीक्षण करने के बाद प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमे स्पष्ट लिखा हुआ है की भवन की हालत अत्यंत जर्जर है और दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ चुकी है। जर्जर भवन में अभी भी स्कूल का संचालन हो रहा है।

# 1991 जैसा आर्थिक संकट, पीएम मोदी को नहीं समझ आ रहा तो कर सकते हैं मदद: राहुल गांधी

**नई दिल्ली।** कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि, ईंधन की कीमतों में जब भी इजाफे की बात कही जाती है तो कह दिया जाता है कि, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में इजाफा हो रहा है, यह बात गलत है। हमारी सरकार थी, तब क्रूड ऑयल की कीमत 105 डॉलर प्रति बैरल था और अब यह 71 डॉलर प्रति बैरल है। उन्होंने आगे कहा कि ,देश के सामने 1991 जैसा ही संकट पैदा हो रहा है। यह अर्थव्यवस्था की समस्या नहीं है बल्कि ढांचागत समस्या है। इससे नीतियों में बदलाव किए बिना बाहर निकला नहीं जा सकता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि, देश के युवाओं को यह सोचना चाहिए कि, यह आपका पैसा है और इसे किसके हाथों में दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि 23 लाख करोड़ रुपए की रकम किन हाथों में जा रही है, इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि, मोनेटाइजेशन प्लान से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के ही 4 से 5 प्रिय मित्रों के हाथों में इसके तहत देश की संपत्ति चली जाएगी।

### अभिव्यक्ति को रोका जा रहा है

महंगाई समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस का विरोध नजर न आने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि, अभिव्यक्ति को रोका जा रहा है। आप जानते हैं कि मीडिया को बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमें संसद में भी रोका जा रहा है। लेकिन इससे गुस्सा बढ़ता जाएगा और रिएक्शन जबरदस्त होगा। राहुल गांधी ने कहा कि, हम लाखों लोगों को लेकर सड़क पर उतर सकते हैं, लेकिन उसके दूसरे खतरे हैं। इसलिए हम ऐसा करने से बच रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को 23 लाख करोड़ रुपए की रकम बढ़े हुए टैक्स से मिली है। आखिर यह रकम कहां जाएगी। हमारी सरकार के दौर में जब 105 डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल था तो देश में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए लीटर थी। आज दुनिया में क्रूड 71 में है तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार है।

## 30 हजार की रिश्वत लेकर भागने वाला एएसआई लोकायुक्त की गिरफ्त में

**धार।** लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना राजोद के एएसआई किशोरसिंह टांक को ग्राम संदला के बस स्टैंड से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एएसआई टांक एक मामले की विवेचना कर रहे थे जिसमें फरियादी का नाम नहीं जोड़ने तथा धारा नही बढ़ाने के बदले में 30 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। बताया जा रहा है कि, रिश्वत लेने के बाद एएसआइ को लोकायुक्त टीम ने पकड़ा वह भागने लगा, लेकिन लोकायुक्त टीम ने उसे पकड लिया। लोकायुक्त टीआई उमाशंकर यादव ने बताया कि, एएसआई टांक ने मौके से भागने की कोशिश की थी, पर टीम ने उसे पकड लिया। लोकायुक्त टीम एएसआइ टांक को सरदारपुर के सर्किट हाउस लेकर पहुंची, जहां आगे की कार्रवाई की गई।

लोकायुक्त टीआई उमाशंकर यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि, फरियादी परमानंद दय्या निवासी लाबरिया द्वारा लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की थी कि राजोद थाने पर पदस्थ एएसआइ किशोरसिंह टांक द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। फरियादी परमानंद दय्या के बड़े भाई का विगत माह समाज के ही कुछ लोगो से विवाद हुआ था। फरियादी के बड़े भाई मोहनलाल दय्या एवं अन्य के विरुद्ध राजोद थाने में धारा 294, 323, 504, 34 भादवी के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था। जिसकी विवेचना एएसआई टांक द्वारा की जा रही थी। प्रकरण में फरियादी परमानंद का नाम तथा धारा नही बढ़ाने के एवज में एएसआई द्वारा 30 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। ग्राम संदला के बस स्टैंड पर जैसे ही एएसआई टांक ने फरियादी परमानंद से रिश्वत ली वैसे ही उसे टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया।

# क्या शराब माफिया अल्केश बाकलिया के गुर्गे के विरूद्ध अब होगी एफआईआर दर्ज...?

## देवझिरी में पकड़ी शराब में आरोपित ने दिए बयान, कालीदेवी से मैनेजर मनोज सिंह ने भरवाई थी शराब और देवझिरी में शंकर नायक को करवाई थी क्रॉसिंग

**माही की गूंज, झाबुआ।**

पुलिस कानून व्यवस्था को अपनी बाप की बपुति मानकर माफियाओं को संरक्षण देकर अपनी कार्रवाई करती है। यहा एक बार नहीं कई बार मय प्रूफ के खुलासे हो चुके हैं, लेकिन स्वार्थ में डूबी खाकी वर्दी के नुमाइंदों ने अपने जमीर बेच माफियाओं के सामने किस तरह नतमस्तक है, जिसका एक और उदाहरण देखने को मिल रहा है 28-29 जून की रात्रि में शराब माफिया अल्केश बाकलिया और मुकेश नायक के निर्देशन में झाबुआ शराब एरिया मैनेजर शंकर नायक रंभापुरी अपने गुर्गो के साथ देवझिरी पहुंचा और अपने दम पर ही प्रतिदिन क्षेत्र में अवैध शराब सप्लाई करने वाला मैनेजर शंकर नायक ने अपने शराब कंपनी के अपने अधिपत्र कर्मचारियों के साथ एक ओमनी कार के साथ शराब की कंपनी में बोलेरो जीप में 20 पेटी माउंट बीयर की अवैध शराब भरकर लाया और मौके से एक नाबालिक को भी उठाकर झाबुआ पुलिस के सुपुर्द कर, अपनी माफियाईराज के आतंक का परिचय देकर ओमनी कार के साथ नाबालिक गोलू के साथ छापरी निवासी मनोज भटेवरा के नाम से अपने कहे अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई।

मामले में आरोपित मनोज भटेवरा फरार होकर न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु अपील की। जमानत नहीं मिलने पर आरोपीत मनोज भटेवरा स्वयं ने झाबुआ कोतवाली पर आकर अपने आप को सुपुर्द किया।

### आरोपीत ने यह दिया बयान

शराब की पुख्ता जानकारी रखने वाले माही की गूंज के सूत्र अनुसार आरोपीत मनोज भटेवरा निवासी छापरी ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि, 28-29 जून की रात्रि में कालीदेवी शराब दुकान के एरिया मैनेजर मनोज सिह ने कालीदेवी विदेशी शराब दुकान से 50 पेटी माउंट बीयर की शराब की पेटियां ओमनी कार में भरवाई थी।

वहीं उक्त शराब देवझिरी तक जाकर झाबुआ शराब दुकान के एरिया मैनेजर शंकर नायक को उसके द्वारा लाई गई गाड़ी में 30 पेटी शराब क्रॉसिंग करवाई थी, वही बची 20 पेटी शराब अन्य दूसरी गाड़ी में शंकर नायक क्रास करवा रहा था कि, दूर से अन्य वाहन आते देख पुलिस के आने की भनक लगने पर फरार हो गए थे। आरोपित मनोज भटेवरा के उक्त पुलिस को दिए बयान के बाद शराब माफियाओं के सामने नतमस्तक हुई पुलिस शराब माफिया अल्केश बाकलिया के गुर्गे शंकर नायक व मनोज सिंह के विरुद्ध क्या मामला दर्ज करेगी...? या अपने जमीर को बेच चुकी पुलिस अभी भी माफियाओं के सामने नतमस्तक ही रहेगी।

उक्त मामले में देखा जाए तो पुलिस को आरोपित के बयानों के आधार पर अल्केश बाकलिया के गुर्गे शंकर नायक व मनोज सिंह के विरुद्ध मामले में आरोपी बनाना चाहिए।

अगर पुलिस अपने आपको राजा हरिश्चंद्र मानकर कहती है आरोपी के बयान गलत है तो अवैध शराब की बोतलों पर बेच नंबर के आधार पर जिस शराब की दुकान से उक्त शराब ढोई गई थी की जांच तक असल में पहुंचती है। तो भी शराब मैनेजर के साथ लाइसेंसी के नाम से मामला पंजिबद्ध हो सकता है।

आखिर क्यों नहीं किया मामला उजागर...?
शराब माफिया अल्केश बाकलिया के गुर्गे शंकर ने पकड़ी शराब, पुलिस ने किया मामला दर्ज

माही की गूंज द्वारा उक्त मामले को उजागर करने के बाद जांच को किस दिशा में ले जाती है, पता नहीं पर यह तय है कि, लाइसेंसी एवं अवैध शराब माफियाओं एवं गुर्गे के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं होता है तो हमारे समाचार को माध्यम बनाकर पुलिस इन माफियाओं से अच्छी खासी रकम वसूल जरूर लेगी...। यह तय है.... !

# सहकारी संस्था में खाद्यान निकासी भ्रष्टाचार का एक नया अध्याय आया सामने

**माही की गूंज, खवासा।**

आदिम जाति सहकारी संस्थाओं में खाद्यान को लेकर कई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आलम उजागर हुए है, जिसमें क्षेत्र के मादलदा-कदवानी एवं बोयडी की सहकारी संस्थाएं में भी गरीबों का अनाज स्वयं आहरण कर भ्रष्टाचार के इस आयाम को हस्ताक्षरित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे कई मामले उजागर भी हुए, परंतु भ्रष्टाचारियों के इस पोले बांस का गठबंधन ऐसा है कि, कभी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

वहीं अब जहां ऑनलाइन खाद्यान्न वितरण की व्यवस्थाओं के साथ हितग्राही अपनी क्षेत्र की सहकारी दुकान के अलावा सुविधा अनुरूप पात्र हितग्राही किसी भी सहकारी दुकान से खाद्यान अपना अंगूठा लगाकर प्राप्त करने की सुविधा शासन ने दी है। परंतु कहते हैं तू डाल-डाल तो मैं भ्रष्टाचारी पात-पात की डाल पर एक कदम आगे चल नई नीति भ्रष्टाचार को आयाम देकर एक नई-नई रचनाएं भ्रष्टाचार रूपी भ्रष्ट रच रहे है। भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना चुके भ्रष्टों ने ऐसा एक खाद्यान्न को अंगूठा लगाकर पूरा के पूरा आहरण कर लिया जिसे सुन विश्वास भी नहीं होता।

थांदला सीसीबी शाखा के अधीन बड़ी धामनी आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था के अधीन बोयडी और मादलदा-कदवाली सहकारी संस्था के सेल्समैनो ने आधार लिंक जोड़ने के नाम पर घर-घर जाकर अंगूठे खाद्यान आहरण वाली मशीन में लगवाकर पूरा का पूरा खाद्यान ही आहरण कर लिया।

उक्त मामला उजागर हुआ की मादलदा ग्राम पंचायत के ग्राम ईटानखेड़ा के 38 परिवार ने अपने परिवार आईडी नंबर के साथ खवासा पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई की कदवानी सहकारी संस्था के अंतर्गत आकर हमारे द्वारा कदवानी से लिया जाता है। लेकिन 25 अगस्त को बोइडी सहकारी संस्था की दुकान का सेल्समैन वीरेंद्र सिंह लक्ष्मीनारायण पवार निवासी खवासा अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को लेकर आया और खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु आधार लिंक आवश्यक है कहकर मशीन में अंगूठा लगवाया, शंका होने पर 30 अगस्त को कदवाली दुकान के सेल्समैन राजेश मैड़ा के पास गए और खाद्यान अगस्त माह का मांगा तो सभी 38 व्यक्तियों का खाद्यान 25 अगस्त को आहरण होना बता दिया, जिसके बाद खवासा चौकी में 38 जनों ने सामूहिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उक्त मामला उजागर हुआ।

मामले में आगे देखने में यह दिलचस्प रहेगा कि, पुलिस व संबंधित अधिकारी इस नए भ्रष्टाचार को आयाम देने वाले भ्रष्ट कर्मचारी के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई करेंगे या फिर पूर्व की तरह संस्थाओं में हुए भ्रष्टाचार की लीपापोती की तरह यहां भी लीपापोती की जाएगी।

मामले में माही की गूंज को ग्रामीण हितग्राही लुणचंद पिता भीमजी भूरिया के साथ ग्रामीण गुलाब सिंह भूरिया, नेरू सिंगाड़, हरचंद भूरिया आदि ने बताया कि, वीरेंद्रसिंह पवार अपने साथी के साथ आकर 38 जनों के अंगूठे आधार लिंक जोड़ने के नाम से मशीन में लगवाए और 38 जनों के खाद्यान सिर्फएक गांव ईटानखेड़ा से ही खाद्यान आहरण कर गरीबों का अनाज खा गए है। कार्रवाई की उम्मीद से आज दिनांक को खवासा चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ग्रामीणों ने बताया कि, हम इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई चाहते हैं। किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम झाबुआ से लेकर भोपाल तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगे।

## प्रधानमंत्री से आगे निकले एसबीआई के गार्ड साहब, रुमाल, गमछे, साड़ी से ढंके चेहरे वालों को बैंक में नहीं दिया जाता प्रवेश

# मास्क के नाम पर बैंक का गार्ड करता है उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार

**माही की गूंज, पेटलावद।**

अपने बुरे व्यवहार के लिए प्रसिद्ध एसबीआई बैंक के स्टाफकी लगातार शिकायतो के बाद भी अपने व्यवहार में कोई सुधार नही करते हुए उपभोक्ताओ से अभद्र व्यवहार जारी रखे हुए है, जिससे कई लोग बैंक के खाते बन्द करवा रहे।

विगत दिनों किसान मोर्चे के पदाधिकारी जितेंद्र पाटीदार द्वारा बैंक में हुए व्यवहार से त्रस्त होकर बैंक में खाता बन्द करने का आवेदन दिया था, जिसमे खाता बन्द करने के लिए के कारण बैंक के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा अभद्र व्यवहार को बताया था। ये कोई पहला मामला नही है कि, बैंक की ओर से उपभोक्ताओं को किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित व परेशान किया गया हो। आए दिन लोग बैंक को लेकर सोशल मीडिया या बाजार में शिकायत करते देखे जा सकते है।

### चाय से ज्यादा केतली गर्म, सिर्फ मास्क वालों को प्रवेश

वैसे तो कोरोना काल मे मास्क हर व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है, लेकिन कोरोना की गाईडलाइन में ऐसा कही नही लिखा है कि केवल मास्क से मुंह ढंके होने पर ही किसी स्थान पर आना-जाना है। व्यक्ति अपने रुमाल, गमछे आदि से भी मुंह ढ़ंक सकते है जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री तक देश को संबोधित करते हुए कर कह चुके है। लेकिन ''चाय से ज्यादा केटली गर्म'' की तर्ज पर प्रधानमंत्री से उपर जाकर बैंक की गेट पर खड़े गार्ड द्वारा बैंक के उपभोक्ताओं को बिना मास्क के अंदर प्रवेश नही करने दिया जाता, जबकि लोगो के मुंह पर मास्क के अलावा रुमाल या गमछे और महिलाओं द्वारा साड़ी व चुन्नी के माध्यम मुंह ढंक कर प्रवेश करने वालो को बैंक के बहार ही रोक दिया जाता है और बहस करने पर अभद्र व्यवहार और किसी भी स्तर तक शिकायत करने की चुनोती तक दी जाती है। ऐसा केवल एसबीआई शाखा में किया जा रहा है जबकि अन्य बैंकों में चहरे पर किसी भी प्रकार के मास्क को वैध मान कर प्रवेश दिया जा रहा है।

### सोशल डिस्टेंस के लिए की व्यवस्था नहीं, ट्रैफिक की व्यवस्था भी बिगाड़ी

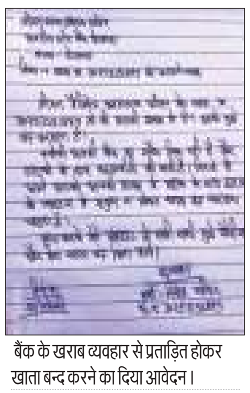
बैंक के खराब व्यवहार से प्रताड़ित होकर खाता बन्द करने का दिया आवेदन।

बैंक के अंदर मास्क ओर सोशल डिटेंसिंग जरूरी, बहार उड़ रही धज्जियां।

कोरोना के नाम पर केवल मास्क वालो को प्रवेश देने का नाटक करने वाली पेटलावद की एसबीआई की शाखा के बहार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती है। बैंक के अंदर तो गिने चुने लोगो को प्रवेश दिया जाता है, जिससे बैंक के बहार भीड़ जमा रहती है। इस पर बैंक का कोई ध्यान नही है। उक्त शाखा रायपुरिया-पेटलावद के मुख्य मार्ग पर स्थित है, जहां उपभोक्ताओं द्वारा अपने वाहन अव्यवथित खड़े कर ट्रैफिक व्यवस्था बिगाड़ी जाती है। अस्पताल पास में होने से कई बार एम्बुलेंस और जननी की गाड़ियां फंस जाती और आए दिन वाहनों से लग रहे जाम के कारण वाहन चालको के बीच विवाद होता है तो कई बार दुर्घटना तक हो जाती है। लेकिन बैंक द्वारा खड़ी हो रही आमजन की परेशानी की ओर बैंक ओर उसके गार्ड की कोई नजर नही जाती है। नगर की एसबीआई शाखा में उपभोक्ताओं को अंदर और बहार दोनों ओर परेशानीयो से जूझना पड़ रहा है जो बैंकिंग व्यवहार और व्यवस्था की बिल्कुल विपरीत है।

## तेज बारिश के बीच मनाया श्री कृष्ण जन्मोत्सव

**माही की गूंज, पारा।** श्री राम मंदिर परिसर मे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर के पुजारी कमलेश वैरागी ने जानकारी देते हुए बताया, इस जयंती के शुभ अवसर पर एक दिन पहले से ही तैयारियां की गई थी। भक्तो द्वारा मंदिर को लाइट डेकोरेशन कर साज-सज्जा की गई। मंदिर परिसर में रंगोली के रंगों से राधा-कृष्ण की रंगोली बनाई गई जो आकर्षण का केंद्र रही। श्री राम दरबार मे कृष्ण भगवान की झांकी बनाकर भक्तो द्वारा सजाया गया। माखन, मिश्री, पंजारी, फल, केसर दूध, पंचामृत, बाल भोग मोतीचूर के लड्डु, श्रीफल, केक, पंच मेवा आदि का भोग लगाकर प्रसादी वितरण की गई। रात 8 बजे के बाद पारा के रामायण मंडल द्वारा भजन मंडली का आयोजन किया गया। गायक पं. संजय शर्मा, चेतन डोडिया, विक्की डोडिया ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन भजनों की प्रस्तुति दी। भक्त भजनों पर रातभर झूमते रहे। तेज बारिश के बीच भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। महाआरती के पश्चात् भक्तो द्वारा 'आलकी के पालकी, जय कन्हैयालाल की'' के जय घोष के साथ प्रसादी वितरण की गई।

## एक माह बिताने को आया, जांच दल अब तक नहीं दे सका अपना प्रतिवेदन

### मामलाः बामनिया पंचायत के दो वर्ष पहले फूटे तालाब का

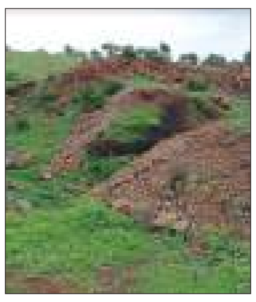

**माही की गूंज, बामनिया।**

ग्राम पंचायत बामनिया में दो वर्ष पूर्व मनरेगा अंतर्गत बने 10 लाख की लागत के तालाब के दो वर्ष पहले फूटने के बाद से अभी तक घटिया निर्माण करने वालो पर कोई कार्रवाई नही हुई, न ही तालाब का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा दौबारा करवाया गया। मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की गई और समाचार प्रकाशित होने के बाद जिला परियोजना अधिकारी मनोज भारस्कर के नेतृत्व में जांच दल 9 अगस्त को आया था, लेकिन जांच दल ने मौके पर केवल जांच के लिए आने का पंचनामा बनाया। मनोज भारस्कर का कहना था कि, रिकॉर्ड देख कर प्रतिवेदन तैयार करेंगे। लेकिन जांच दल के लगभग एक माह के करीब होने आया लेकिन जांच दल ने अब तक अपनी और से प्रतिवेदन नही दिया है। मनरेगा परियोजना अधिकारी मनोज भारस्कर का कहना है कि, हमने तालाब निर्माण की पूरी फाइल, एमबी, बिल बाउचर और रिकॉर्ड लाने को कहा था, लेकिन अब तक रिकॉर्ड नही उपलब्ध नही करवाया गया, जिसके कारण प्रतिवेदन नही बन पाया है। जल्द प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि अधिकारी मौखिक रूप से भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की पुष्टि कर चुके है।

### भाजपा जिला मंत्री से जुड़ा मामला, रफा-दफा करने की कोशिश

ग्राम पंचायत बामनिया की सरपंच रामकन्या मखोड वर्तमान में जिला भाजपा मंत्री हैं। जिसके चलते मामले में राजनीतिक दबाव बनाकर दबाने की जानकारी भी मिल रही है। बताया जा रहा है, अधिकारी दबाव के चलते प्रतिवेदन बनाकर नही दे रहे है।

# यातायात सप्ताह में ढकोसला करने वाली जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी करवा रही बाल मजदूरों से मजदूरी

## कंपनी से वसूल रहे 300 रुपए मजदूरों को दे रहे हैं 200 रुपए

**माही की गूंज, खवासा।**

कोई भी संस्था जिस तरह से आम लोगों को सार्वजनिक रूप से पूरे नियम के आधार पर कार्य करने को बाध्य है स्वयं को उजागर करता है और रही बात भ्रष्टाचार के साथ-साथ सभी नियमों को ताक में रखकर कार्य करता है तो इसकी कथनी और करनी की कार्यशैली आम जनता के सामने आ ही जाती है।

भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा दिल्ली-मुंबई 8 लाइन एक्सप्रेस वे मार्ग का कार्य रतलाम जिले से गुजरात तक जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जयपुर राजस्थान की कार्य कर रही है। कम्पंनी के जितने बड़े नाम है उतना ही बड़ा घटिया कार्य सामने एक के बाद एक आ रहा है। पिछले वर्ष जीआर इंफ्रा कंपनी द्वारा यातायात सड़क सप्ताह के अंतर्गत कैंप का आयोजन कर आम जनता को यातायात अधिनियम का पालन करने का एवं यातायात अधिनियम के तहत नाबालिक को वाहन नहीं चलाने का संदेश देकर जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने आम लोगों के सामने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि, कंपनी 8 लेन मार्ग का जो कार्य क्षेत्र में किया जा रहा है वह शासन के नियमानुसार है। ताकि कोई आम जनता इसके अर्नगल कार्य की ओर कोई ध्यान नहीं देगा की सोच के साथ लोगों को गुमराह करने के साथ यातायात सप्ताह का संदेश देने हेतु कैंप आयोजित किए गए थे। इसी बात से सिद्ध हो रहा है कि, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियो को ही यातायात सड़क सुरक्षा का पालन करवाना तो ठीक, कंपनी के कर्मचारियों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया, इतना ही नहीं क्षेत्र में बड़े रूप से अवैध मोरम का खनन कर शासन को करोडो का चूना लगाया। वही जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी में कार्य करने वालों ने क्षेत्र की महिला पर बुरी नजर डाली तो वही सीधी-साधी लड़की को अपने जाल में फंसाकर भगाकर ले गया और लड़की मौत के घाट तक उतर गई। कर्मचारियो द्वारा ऐसे अनैतिक व अर्नगल कार्य करने वाली कंपनी से और ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। वह अपने कार्य में दखल देने वालों पर या उनके खिलाफ किसी भी निचले स्तर पर उतर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

### पत्रकार के विरुद्ध मजदूरों को भड़काने का कृत्य कर रही कंपनी

8 लेन एक्सप्रेसवे के कैंप 24 के अंतर्गत रत्नी से मुजाल्दा तक कार्य में डिवाइडर स्पेस में पौधे लगाने का कार्य चल रहा है, उक्त कार्य में नाबालिग मजदूरों से कार्य करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि, जीआर इंफ्रा कंपनी ने उक्त कार्य पेटी कांट्रेक्टर के रूप में कॉसमॉस कंस्ट्रक्शन कंपनी को कार्य दिया है और प्रति मजदूर 300 रूपए के हिसाब से मजदूरों को मजदूरी देना तय किया है। लेकिन कंपनी का सुपरवाइजर संदीप रघुवंशी नाबालिग मजदूरों को कार्य पर रखकर 150 से 200 रूपए तक की मजदूरी के साथ बाल श्रम अधिनियम का भी मखोल उड़ाने के साथ ही कंपनी की गाइडलाइन को भी पलीता लगाने में कोई चूक सुपरवाइजर संदीप रघुवंशी नहीं कर रहा है।

मामले में जानकारी जब क्षेत्र के पत्रकारों को लगी तो मौके पर पहुंचे। पत्रकारों के कैमरे में बाल मजदूर कार्य करते हुए कैद हुए, सुपरवाइजर रघुवंशी के साथ कंपनी के अन्य कर्मचारियों व नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंजीनियर तक हरकत में आए और जब उनके पास कोई जवाब नहीं मिला तो, कंपनी के इन जवाबदारो ने मजदूरों को बर्गलाकर कहा कि, पत्रकार अब आपको मजदूरी देगा हम काम पर नहीं रखेंगे, कहकर पत्रकारों के विरुद्ध मजदूरों को भड़काया गया। लेकिन मजदूरों को पता चला कि, पत्रकार मजदूर वह बाल श्रमिकों के हक में कार्य करता है और उनके साथ कंपनी द्वारा दिए जाने वाले 300 रूपए की जगह मजदूरों को 150 से 200 रूपए ही दिए जा रहे हैं। तो सभी मजदूर जनहित में खड़े होकर पत्रकार को कंपनी की वास्तविकता बताई। वहीं अब भी कंपनी के जवाबदार अन्य गांव बदल-बदलकर वहां के नाबालिग मजदूरों को सस्ते भाव में मजदूरी करवा कर अपना कार्य करवा रहे हैं। जिन मजदूरों को कंपनी की कथनी और करनी में फर्क देख मजदूर अपनी बात करता है तो उन मजदूरों को फटकार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है पत्रकार मजदूरी पर रखेंगे हम नहीं रखेंगे यह कहकर रवाना तक कर दिया जा रहा है।

इस संबंध में नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के रतलाम हेड ऑफिस के सब इंजीनियर अजहर खान के मोबाइल नंबर 7974794043 पर माही की गूंज कार्यालय से संपर्क किया, परंतु साहब के पास कोई जवाब नहीं होने के कारण ट्रूकॉलर में माही की गूंज को देखकर एक से अधिक बार किए फोन को उन्होंने अटेंड नही किया।

## क्या यही है प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान...

# कोरोना महामारी से भी प्रशासन ने नहीं लिया सबक

## कलेक्टर की जानकारी में आने के बाद भी ग्राम में लगे हुए गंदगी के ढेर

**माही की गूंज, पेटलावद/झकनावदा।**

पेटलावद जनपद का एक गांव ऐसा भी हैं जहां पर न कोई सुनने वाला है, न कोई देखने वाला है, और न ही कोई कहने वाला है। जी हां हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत झकनावदा की जहां पर चारों तरफगंदगी का आलम है। रोड पर गंदा पानी जमा हुआ है जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां डेंगू, मलेरिया, टाइफ़इड, चिकनगुनिया, जैसी बीमारियां हो रही है, इस ओर स्वास्थ्य विभाग का न कोई ध्यान है और न हीं जिला प्रशासन का। नगर में फैली गंदगी के मुद्दे को माही की गूंज के अखबार के पिछले अंक में ÷समस्याओं से ग्रसित ग्राम को हरा-हरा बताने वाले स्वार्थियों को कलेक्टर व मंत्री ने सम्मानित कर सम्मान को किया अपमानित÷ शीर्षक के साथ खबर को प्रकाशित कर जिले के अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया था। लेकिन स्थानीय बस स्टैंड पर गंदगी ज्यों की त्यों बनी हुई है, शौचालय के सामने प्लास्टिक की पन्नीया व भारी गंदगी फैली हुई है और रोड पर पानी भरा हुआ है, न जिला प्रशासन का इस ओर ध्यान है और न ही स्वास्थ्य विभाग का, तभी तो ग्राम में अनेक संक्रमित बीमारियों ने अपना जाल बिछा रखा है। लोग इलाज के लिए निजी क्लीनिकों पर एवं सरदारपुर, धार, दाहोद, बड़ौदा, जाने को मजबूर है।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया स्वच्छता अभियान का संदेश झकनावद पंचायत या उनके जिम्मेदारों तक नही पहुँच सका...? जिसके कारण आज भी ग्राम की आम जनता नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और जिला प्रशासन है कि कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है।

### कलेक्टर का इस ओर कोई ध्यान नहीं, समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई

माही की गूंज अखबार में खबर प्रकाशित हुए आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं, परंतु जिला प्रशासन के मुखिया है कि, सुध लेने को तैयार नहीं लगता है और चुपचाप आंख मूंदकर बैठे हैं। इन सारी समस्याओं को देखते हुए जिला कलेक्टर को जल्द से जल्द निराकरण करवाने की पहल करनी थी, वहां कलेक्टर की और से भी किसी प्रकार की कोई हलचल नही देखी गई। उल्टा ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित कचरा वाहन जो एक दिन छोड़ कर कचरा उठता था उसे अब हफ्ते में बमुश्किल एक या दो दिन ही संचालित किया जा रहा है।

उक्त समस्या से अवगत करवाते हुए कलेक्टर को भी मोबाइल द्वारा जानकारी दी गई लेकिन मामले में सख्त कदम उठाने और ग्राम पंचायत को कड़े दिशा निर्देश देने की बजाए सीईओ पेटलावद से संपर्क कर समस्या बताने की बात कही गई। जिससे साफपता चलता है कि, स्वच्छता अभियान को लेकर जिला कलेक्टर कितने सजग है।

### स्वास्थ्य विभाग भी बड़ी महामारी का कर रहा इंतजार

इधर ग्राम पंचायत और जिला कलेक्टर गंदगी को लेकर कोई उचित कदम नही उठा रहे है, वही स्वास्थ्य विभाग की पोल-पट्टी के कारण आज झकनावदा में हर घर में लोग मौसमी बीमारियों से पीड़ित हैं। चारों ओर ग्राम में गंदगी ही गंदगी फैली हुई है, न स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्लीचिंग पाउडर नालियों में डाला जा रहा है, और न हीं क्लोरीन की गोलियां पानी को स्वच्छ बनाने के लिए ग्राम में वितरित की जा रही है। तभी तो क्षेत्र में इस समय घर-घर बीमारियों ने दस्तक दे रखी है। स्वास्थ्य विभाग ने केवल और केवल अपनी औपचारिकता पूरी की है। गूंज में खबर प्रकाशित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर सर्वे किया गया कि, आपके यहां पानी की टंकी है या नहीं? आपके घर के आस-पास पानी एकत्रित तो नहीं हो रहा है? केवल और केवल खानापूर्ति पूरी की गई, न किसी को पानी में डालने के लिए क्लोरीन की गोलियां दी ओर न ही ब्लीचिंग पाउडर दिया, न तो पानी की टंकी को देखा गया। यह है स्वास्थ्य विभाग का सर्वे, केवल और केवल आंकड़े पूरे किए जाते हैं धरातल पर कोई काम नहीं किया जाता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि, कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर माह में आने वाली है एवं बच्चों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आलम यह है कि, स्वास्थ विभाग केवल रिकॉर्ड ही रख रहा है। सर्वे को लेकर केवल और केवल औपचारिकता ही पूरी की जा रही है। ऐसे में ग्रामीणों का क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। परंतु समय रहते हैं स्वास्थ्य विभाग अगर नहीं जागा तो फिर तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता।

# हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग

**माही की गूंज, पेटलावद।**

प्रदेश में हो रही हिंसात्मक घटनाओं को संज्ञान में लेकर अपराधियों को फांसी जैसा कठोर दंड दिलवाने के संबंध में जनजाति विकास मंच तहसील पेटलावद द्वारा मंगलवार को गृहमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल, कलेक्टर झाबुआ, पुलिस अधीक्षक झाबुआ, एसडीएम पेटलावद, थाना प्रभारी पेटलावद के नाम ज्ञापन दिए। ज्ञापन में मांग की गई कि, ग्राम नरोला हीरापुर तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर की 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 22 अगस्त को ग्राम नरोला के शकील खान, शहाबुद्दीन, इकबाल खान सहित अन्य अज्ञात लोगों द्वारा रात को अपहरण कर लिया था। जिसका नरोला तालाब में 25 अगस्त की रात्रि में संदिग्ध अवस्था में शव पाया गया था। इस घटना से संयुक्त माली समाज में बहुत आक्रोश व्याप्त है तथा उस बालिका के साथ में दरिंदों ने अमानवीय कृत्य किया है। इसके लिए आरोपियों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए ओर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

नीमच जिले के सिंगोली में कन्हैयालाल के साथ मारपीट कर पिकअप से बांध कर सड़क पर घसीटा गया, जिससे कन्हैयालाल की मौत हो गई ओर गरीब आदिवासी को जाति सूचक शब्द बोल कर प्रताड़ित किया, जिससे पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है। प्रशासन द्वारा उक्त घटना के सभी अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ कर फांसी की सजा दी जाए। शासन-प्रशासन द्वारा अपराधियों के खिलाफकठोर कार्रवाई नहीं होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद है और पूर्व में भी ऐसी घटनाएं प्रदेश में हो चुकी है। शासन-प्रशासन द्वारा इन घटनाओं को संज्ञान में लेकर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश के साथ पूरे देश में जातिगत आंदोलन करने की चेतावनी भी ज्ञापन में दी गई। लगातार बढ़ रही घटनाओं से पूरे प्रदेश में अशांति का माहौल बन गया है। ज्ञापन देते समय जनजाति विकास मंच के समस्त कार्यकर्ता मौजूद थे।

## नया गुजराती लौहार समाज जिलाध्यक्ष नियुक्त

**माही की गूंज, खवासा।** समाज को नई दिशा देना एक महत्वपुर्ण उद्देश्य होता है, वहीं समाज व संगठन में परिवर्तन एवं नियुक्ति होना एक समय उपरांत के बाद समाज व संगठन के हित का प्रतिक माना जाता है। इसी उद्देश्य के साथ नया गुजराती लौहार समाज राष्ट्रीय सेक्टर उज्जैन के अधिन झाबुआ जिले के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व नवीन कमेटी नियुक्ति हेतु सुन्दर गार्डन पेटलावद में एक बैठक समाज के प्रबुद्धजनो की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज की अपनी आचार संहीता अनुरूप समाज को नई दिशा व मजबुती दिलाने के साथ नवगठित कमेटी हेतु उक्त विशेष बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में समाज के तीन प्रबुद्ध व कर्मठ व्यक्तियों ने अध्यक्ष पद के साथ समाज विकास व समाज को नई दिशा देने के लिए अपनी सक्रियता का परिचय दिया। समाज व संगठन की अपनी आचार संहीता अनुरूप एक को ही उक्त पद का दायित्व देने का निर्धारण सुनिश्चित होने के साथ सामाजिक सदस्यों के मतदान के साथ खवासा निवासी नया गुजराती लौहार समाज के सक्रिय सदस्य शैतानमल लौहार को झाबुआ जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। उक्त नियुक्ति के साथ समाज के सभी सम्मानजनों ने श्री लौहार को माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही समाजजनों ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शैतानमल लौहार से अपेक्षा की है कि, वे समाज की उम्मीदों पर खरा उतरकर तन-मन-धन से अपना अमुल्य समय देकर समाज को नई दिशा प्रदान करेंगे। माही की गूंज से चर्चा के दौरान नया गुजराती लौहार समाज के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शैतानमल लौहार ने बताया कि, समाज द्वारा जो अपेक्षाएं समाज को जाग्रत कर समाज को नई दिशा प्रदान करने की अपेक्षाओं के साथ मुझे जो दियित्व दिया है, उस दायित्व पर तन-मन-धन के साथ खरा उतरकर समाज उत्थान के लिए तत्पर रहुंगा।

# धूमधाम से मनाया कृष्ण जन्मोत्सव, निकली बांसुरी यात्रा

**माही की गूंज, थांदला।**

जन्माष्टमी पर्व पर नगर मे चारों हर्ष और उल्लास छाया रहा। नगर के बांके बिहारी मंदिर, चारभुजानाथ व सांवरिया सेठ मंदिर पर भगवान राधा-कृष्ण का विषेश आर्कषक श्रृंगार किया गया तथा मंदिरो मे साज सज्जा की गई। दिनभर मंदिरो मे श्रृद्धालुओ का तांता लगा रहा। बांके बिहारी मदिर मे भजन संध्या व सांवरिया सेठ मंदिर पर बच्चो की मटकी फोड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छोटे बच्चे कृष्ण रूप के परिधान पहनकर आर्कषण का केन्द्र बने हुए थे।

क्षैत्र के जनजाति विकास मंच व अखिल भारतीय संत समिति ने धर्म व संस्कृति का संगम करते हुए बांसुरी यात्रा का आयोजन किया। यात्रा संयोजक संजय भाबर ने बताया कि, ग्राम चेनपूरी से प्रारंभ होकर यात्रा बावडी मंदिर पर समपन्न हुई। अचंल की आदिवासी संस्कृति बांसुरी वादन का भी अपना अलग महत्व है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ अंचल में आदिवासी समाज के लोग प्रकृति से अपने जुडकर आंनद की अभिव्यक्ति के रूप मे बांसुरी वादन करते है। उनकी इस संस्कृति को धर्म से जोडकर हमने जन्माष्टमी के अवसर बासुरी यात्रा का अभिनव आयोजन किया। यात्रा मे काफी संख्या मे समाजजन अपनी पारंपरिक बांसुरी बजाते हुए यात्रा का आर्कषण बने हुए थे। एक साथ दर्जनो बांसुरी की स्वर लहरीयो को सुनकर लोग आंनदित हो रहे थे। इस अभिनव आयोजन को लोगो ने काफी सराहा यात्रा मे क्षैत्र के संतगण भी सम्मिलित थे।

## नुक्कड़ नाटक के साथ लोगों को कर रहे जागरूक

**माही की गूंज, झाबुआ।** महिला एवं बाल विकास की और से आग़ाज कार्यक्रम के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का आयोजन जिले में किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगो को जागरूक किया जा रहा है। योजना अनुसार बच्चों के साथ हो रहे लैंगिक अपराध, बाल विवाह, बाल सरक्षण, बाल शिक्षा, गर्भवती एवं चाईल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098, 100, 108 के बारे में जागरूक कर लोगो को बताया जा रहा है कि, किस तरह से बच्चो की हर समय मदद को चाईल्ड लेल्प लाईन पर जानकारी मिलने के प्रशासन तैयार रहता है।

कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने 12 अगस्त को कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की थी। इस टीम झाबुआ जिले के 200 गांवो जाना है। गांवो में जाकर ग्रामीणों को नुकड़ नाटक कर उन्हें सामुदायिक जागरूकता कर रहे हैं। इसी के साथ लोगो को मास्क, बाल संरक्षण के पर्चे भी बांटे ओर कोरोना गाईडलाइन का पालन करने के लिए टीम को वॉलिंटियर कर रहे। ब्रजेश नायक अपनी पूरी टीम लो लेकर गांव-गांव में जाकर ये नुकड़ नाटक करवाते है।

## शिशु रोग विशेषज्ञ के स्थानान्तरण से चरमराई सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्था

**माही की गूंज, थांदला।**

अंचल को काफी लम्बे समय से अपनी सेवाए दे रहे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. कमलेश परस्ते के स्थानान्तरण से सिविल हास्पिटल के शिशु रोग विभाग की व्यवस्थाए चरमरा गई। अस्पताल मे निमोनिया, सर्दी-जुकाम के मरीजो की भीड लग रही है, जिसमे छोटे बच्चो की सख्या अधिक है। मौसम के उतार-चढाव से क्षेत्र मे मौसमी बीमारीयो और सर्दी, बुखार के मरीजो की संख्या प्रतिदिन बढ रही है, ऐसे समय में शिशु रोग विषेषज्ञ के नही होने से काफी परेशानी हो रही है।

गौरतलब है कि, डॉ. कमलेश परस्ते हास्पिटल मे काफी वर्षो से पदस्थ थे और इनके उपचार से क्षेत्र के लोग संतुष्ट थे। किन्तु पारिवारिक परेशानीयो के चलते उन्होने अपना स्वैच्छिक स्थानान्तरण शहडोल जिले मे करवा लिया। इनकी पत्नी भी आयुष विभाग मे पदस्थ होकर उनका स्थानान्तरण पूर्व मे ही शहडोल हो चुका है। सिविल हास्पिटल मे एक शिशु रोग विशेषज्ञ की नितांत आवश्यकता बनी हुई है। प्रशासन क्षैत्र की आवश्यकता को देखते हुए शिशु रोग विशेषज्ञ को पदस्थ करे, अन्यथा बीमारीयो के दौर मे लोगो को दाहोद, रतलाम, इंदौर आदि शहरो के निजी चिकित्सालयो पर निर्भर होना पडेगा।

## पुलिस से हुज्जतबाजी के बीच युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका

**माही की गूंज, झाबुआ।**

मप्र युवक कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया के निर्देश पर संपूर्ण प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर नीमच में एक ग्रामीण को वाहन के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटने और घटना के कुछ समय बाद ग्रामीण की मृत्यु होने के चलते मप्र सरकार और उसके मुखिया शिवराजसिंह चौहान द्वारा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं करने से नाराज होकर बुधवार को विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन कार्यक्रम रखा।

जिला मुख्यालय झाबुआ पर भी युथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय भाबर एवं झाबुआ विधानसभा अध्यक्ष हेमेन्द्र बबलू कटारा के नेतृत्व में बस स्टेंड स्थित फव्वारा चौक पर नीमच की घटना को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ एवं प्रदेश के मुखिया तथा गृह मंत्री के खिलाफ भी जमकर हाय-हाय के नारे लगाए गए। इस बीच बस स्टेंड चौकी के पीछे से पुतला आने पर पुलिस की हुज्जबाती एवं कड़े विरोध के बीच युथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने मिलकर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। इस दौरान मौके पर फायर ब्रिगेड़ भी मौजूद रहीं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों में नायब तहसीलदार सुनिल डावर, एसडीओपी ईडल मोर्य, थाना प्रभारी झाबुआ सुरेन्द्रसिंह गाडरिया, एसआई महावीर सहित बड़ी संख्या में अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं नगरपालिका की ओर से राजस्व शाख से अयूब खान, अमित भाबर आदि भी उपस्थित रहे।

# गड्ढों से पटी सड़क पर सफर, कमर तोड़ता भारी भरकम टोल टैक्स

## पिटोल से राजगढ़ तक 60 किमी का सफर हिला देता शरीर का पुर्जा-पुर्जा

## माछलिया घाट की स्थिति तमाम कवायदों के बाद भी ढाक के तीन पात

**माही की गूंज, झाबुआ। मुज्जमिल मंसुरी**

फरवरी माह में झाबुआ कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा बैठक में माछलिया घाट पर डेंजर जोन क्षेत्रों में चौड़ीकरण कर जाम से छुटकारा दिलाने के लिए कलेक्टर ने निर्देशित किया था। गर्मागर्मी में कलेक्टर के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमले ने घाट का मौका मुआयना किया और काम शुरू हुआ। पूरे घाट में केवल दो ही जगहों पर पहाड़ी की खुदाई व रोड समतलीकरण का कार्य किया गया। बैठक में घाट के कई मोड़ों पर पैवर लगाने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन एक या दो जगहों पर ही यह काम कछुआ गति से हुआ। उद्देश्य तो यह था कि घाट में लगने वाले जाम से आमजनों को राहत मिलेगी। आज 6 माह बीत जाने के बाद माछलिया घाट की स्थिति ढाक के तीन पात ही नजर आ रही है। जिस उद्देश्य को लेकर प्रशासन ने इतनी जद्दोजहद की वह आज सिफर ही नजर आ रही है। माछलिया घाट आज भी सड़क पर गड्ढों से पटा पड़ा है और घाट में लगने वाले जाम की स्थिति भी यथावत बदस्तूर जारी है।

5 किलोमीटर के माछलिया घाट में 15 से अधिक घुमावदार मोड़ है। इनमें से भी 4 या 5 डेंजर डोज है। जहां बड़े वाहन आते ही मार्ग के दोनों ओर जाम लग जाता है। जिससे यात्रा करने वालों का सफर कई घंटों ज्यादा लंबा हो जाता है। फरवरी में हुई सड़क सुरक्षा बैठक में अधिकारियों ने कई फैसले करते हुए संबंधित एजेंसियों के ठेकेदारों को रोड मरम्मत के साथ नवीन रोड निर्माण करने के निर्देश दिए थे। मगर अब माछलिया घाट की स्थिति जस की तस बनी हुई है। माछलिया घाट पर जाम लगने का मुख्य कारण घाट के नीचे बनी दशकों पुरानी सकरी पुलिया भी है जिस पर से दो वाहन एक साथ नही गुजर सकते। जब एक ही समय में इस पुलिया पर आमने-सामने वाहन आ जाते है तो दुर्घटना के भय के साथ जाम की स्थिति बनना लगभग तय हो जाता है। चूंकि यह मार्ग राष्ट्रीय राज मार्ग होने व मध्यप्रदेश को सीधा गुजरात से जोड़ने के कारण इस पर वाहनों का दबाव अधिक होता है, और कुछ ही देर में यहां वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। घाट के चार से पांच घुमावदार मोड़ों पर भी ऐसी ही स्थिति निर्मित होती है। प्रशासन से इन मोड़ों से सटी पहाड़ियों को खोदकर चौड़ा तो किया लेकिन समतलीकरण व मिट्टी के दबाव के अभाव में प्रशासन द्वारा किए गए कार्य शुन्य ही साबित हुए है। घाट के जिन हिस्सों में पहाड़ी काटी गई है, उस कच्चे हिस्से में भारी वाहन उतर ही नहीं सकते। बारिश का समय होने के कारण वाहन चालक भी सड़क से वाहन को नीचे उतारने में संकोच करते है। क्योंकि भारी वाहन कच्ची व नमी वाली जगह से निकालने में मिट्टी दबने के कारण वाहन के फंसने का ज्यादा डर बना रहता है। जिससे घंटों जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है।

राजगढ़ से पिटोल के मध्य अधूरे पड़े राष्ट्रीय राज मार्ग के अधूरे हिस्से में सड़क के गड्ढों में इस तरह भरी जा रही मुर्रम।

खाखरा पुलिया पुरानी होने के साथ-साथ जर्जर अवस्था में है, यहां भी गड्ढों में सिर्फ मार्रम ही भरी जा रही है।

वैसे अगर माछलिया घाट की समस्याओं को छोड़ भी दें तो पिटोल से राजगढ़ जाना वर्तमान स्थिति में 'नाको चने चबाने जैसा ही है।' कारण यह कि राजगढ़ से पिटोल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब भी 16 किलोमीटर का हिस्सा अधूरा ही पड़ा हुआ है। इसके अलावा पिटोल से लेकर राजगढ़ तक इस मार्ग पर गहरे होते जा रहे गड्ढों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस 60 किलोमीटर के सफर से इस मार्ग पर यात्रा करने वालों की कमर ढीली हो जाती है, लेकिन इस खस्ताहाल 60 किमी की सड़क पर सफर करने के दौरान उसे भारी भरकम टोल देना पड़ता है, जो उसकी कमर तोड़ देता है। छोटो वाहनों को यहां एक बार एक तरफ का 145 रुपये टोल चुकाना पड़ता है। भारीभरकम टोल लेने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की इस सड़क का रख-रखाव करने में भारी उदासीनता टोल कंपनी द्वारा दिखाई जा रही है। धार-झाबुआ जिला प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग की समस्या को अनदेखा कर अपनी उदासीनता को जग जाहिर कर रहे है।

बारिश के बाद से ही इस राष्ट्रीय राजमार्ग ही हालत खराब होने लगी थी। दिन-ब-दिन इस मार्ग की हालत बद से बदतर होती चली गई। किसी भी जिम्मेदार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अब हालत कमर तोड़ देने वाली हो चुकी है। जबकि जिले के आला अधिकारियों का इस मुख्य मार्ग पर अक्सर आना-जाना लगा रहता है। मगर राष्ट्रीय राजमार्ग की इस हालत पर जैसे किसी को कोई लेना -देना ही नहीं। पड़ोसी राज्य गुजरात की सड़कों और मध्यप्रदेश की सड़कों में अंतर महज बार्डर पार करते ही समझ आ जाता है। जिलेवासी तो जिम्मेदारों की लापरवाही के इस दंश को कसमसा कर झेल लेते मगर गुजरात से आने वाले यात्री मध्यप्रदेश के इस 60 किलोमीटर के सफर में मध्यप्रदेश सरकार के साथ जिला प्रशासन को भी कोसते व बद्दुआएं ही देते नजर आते। वजह बिल्कुल साफ है कि गुजरात की सड़कों पर उनके पेट का पानी तक नहीं हिलता और मध्यप्रदेश में प्रवेश करते कि शरीर का पुर्जा-पुर्जा इस 60 किलोमीटर के सफर में हिल जाता। विडंबना यह कि इंदौर से पिटोल तक 171 किलोमीटर का यह राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 8 सालों में भी पूर्ण नहीं हो पाया। अब जाकर सुगबुगाहट सुनाई दे रही है कि अधूरे पड़े इस मार्ग का सितम्बर माह से कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन यह भी समय के गर्त में है कि यह पूरा कब तक होगा। और जब तक यह पूरा नहीं होता इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने वालों की कमर टूटती ही रहेगी। हां इतना जरूर है कि खानापुर्ति के लिए इस मार्ग के गड्ढों को मुर्रम से भर जाता रहा है। मगर बारिश के भादो माह के जोरदार बारिश के सेरों को यह गड्ढों में भरी मुर्रम कब झेल सकती है, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

## संपादकीय

# कोरोना से लंबी लड़ाई के लिए सतर्कता जरूरी

हम देश की उस दोहरी उपलब्धि पर गर्व करें, जिसमें हमने लक्षित आबादी के आधे लोगों को एक वैक्सीन लगा दी है और एक दिन में एक करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य हासिल किया। देश ने नब्बे करोड़ वयस्क आबादी को कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने हेतु टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। पिछले दिनों हमने इसमें से आधी आबादी को टीका लगा दिया। हालांकि अभी पंद्रह फीसदी आबादी को ही दोनों टीके लगे हैं। गत सोलह जनवरी को शुरू हुए टीकाकरण अभियान में यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह ने उम्मीद जगाई है कि, सवा करोड़ टीके एक दिन में लगाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इस उम्मीद का आधार यह है कि, पहले दस करोड़ टीके जहां 85 दिन में लगे, वहीं पचास से साठ करोड़ टीके लगने में महज 19 दिन लगे। टीकाकरण का अनुभव व टीकों की उपलब्धता भी इसमें सहायक साबित होगी। निःसंदेह यह हमारे स्वास्थ्य तंत्र की बड़ी उपलब्धि है।

दरअसल, 31 दिसंबर तक देश की वयस्क आबादी के टीकाकरण लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोज एक करोड़ लोगों को टीका लगाने की जरूरत है। लेकिन अक्तूबर में तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच टीकाकरण के उच्च लक्ष्य हासिल करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसमें केंद्र के साथ ही राज्यों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। यह अच्छी बात है कि, अगस्त माह में टीकाकरण अभियान में हमने आशातीत सफलता हासिल की है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र सबसे आगे हैं। हिमाचल में भी 99 फीसदी लक्षित आबादी को एक टीका लग चुका है। राज्य ने तीस नवंबर तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। देश में 63 करोड़ लोगों को अब तक एक टीका लग चुका है। हालांकि, यह चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन पूरी आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य अभी चुनौती है। फिर भी हम न भूलें कि, कोरोना संक्रमण का आंकड़ा पिछले दो माह में सर्वाधिक पैंतालीस हजार से ऊपर पहुंचा है। इसी चिंता के चलते मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों समेत कई कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों का दायरा सितंबर तक बढ़ा दिया। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार तीसरी लहर को लेकर चेता रहे हैं। वैसे तो कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में आया उछाल केरल में तेजी से बढ़ते आंकड़ों की वजह से है, लेकिन शेष देश को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। केरल सरकार से पूछना चाहिए कि, तुष्टीकरण के चलते एक धार्मिक आयोजन पर कोरोना कर्फ्यू में तीन दिन की छूट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को नजरअंदाज करके क्यों दी गई थी? क्यों कोरोना महामारी से सफलता से जूझने वाली स्वास्थ्य मंत्री को हटाया गया, जिसके प्रयासों की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तारीफ की थी? साथ ही महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में संक्रमण की बढ़ती दर चिंता की बात है।

दरअसल, कोरोना संक्रमण में आई गिरावट को देखते हुए हमने मान लिया कि, शायद कोरोना की विदाई हो गई। हमने बचाव के प्राथमिक उपायों, मसलन मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी और साबुन से हाथ धोने की अनदेखी शुरू कर दी। चिंता की बात यह है कि, देश में रक्षाबंधन व जन्माष्टमी के साथ ही त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो गई है। जिस अवधि में तीसरी लहर की आशंका है, उसमें पितृपक्ष, नवरात्रों, दशहरा व दीपावली की पर्व श्रृंखला शुरू होती है। वहीं स्कूल-कॉलेज खोलने का सिलसिला शुरू हो गया है। बच्चों के लिए देश में निर्मित वैक्सीन क्लीनिकल ट्राइल में तो सफल रही है लेकिन टीका उपलब्ध होने में वक्त लगेगा, तब तक सावधानी ही विकल्प है। निश्चित रूप से त्योहारी माहौल में लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। अमेरिका-यूरोपीय देशों में ऐसी लापरवाही के चलते कोरोना संकट एक बार फिर गंभीर हुआ है। जब तक हम लक्षित आबादी को दोनों डोज उपलब्ध नहीं करा देते, तब तक कोविड-19 से हमारी लड़ाई जारी रहनी चाहिए।

# जन कल्याण में बाधा न बनें सरकारी नौकरियां

संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी। यह कहने की जरूरत नहीं कि, जनकल्याण हासिल करने के लिए सरकारी कर्मियों की नियुक्ति करनी ही होगी। जैसे हाईवे बनवाने के लिए अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए सरकारी कर्मियों की नियुक्ति करना आवश्यक होता ही है। सोच है कि, सरकारी कर्मी अपने कार्यों का निष्ठापूर्वक सम्पादन करके देश के आर्थिक विकास में योगदान देंगे और जनकल्याण हासिल करेंगे। लेकिन यदि सरकारी कर्मियों को सरकार इतना अधिक वेतन देने लगे कि विकास और जनकल्याण दोनों ठप हो जाएं तो हम संविधान की भावनाओं के विपरीत चल पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मियों का कल्याण प्राथमिक और जनकल्याण गौण हो जाता है।

विश्व बैंक ने 'वैश्विक परिदृश्य में सरकारी वेतन' नाम से अध्ययन किया। इसके अनुसार वियतनाम में देश के नागरिक की औसत आय की तुलना में सरकारी कर्मी का औसत वेतन 90 प्रतिशत होता है। यदि वियतनाम के नागरिक की औसत आय 100 रुपए है तो सरकारी कर्मी का औसत वेतन 90 रुपए है। चीन में यदि नागरिक का औसत वेतन 100 रुपए है तो सरकारी कर्मी का औसत वेतन 110 रुपए बैठता है। लेकिन भारत में यदि नागरिक का औसत वेतन 100 रुपए है तो सरकारी कर्मी का औसत वेतन 700 रुपए है। यह बात विश्व बैंक की रपट बताती है। वियतनाम और चीन के नागरिक का औसत वेतन आज भारत की तुलना में अधिक है। लेकिन जब इन देशों के नागरिक का औसत वेतन भारत के समतुल्य था तब भी सरकारी कर्मियों का वेतन इसी अनुपात में था। गौर करने की बात यह है कि, वियतनाम और चीन दोनों ही हमसे बहुत अधिक तीव्रता से आर्थिक विकास हासिल कर रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि, भारत की आर्थिक विकास दर के न्यून होने के पीछे एक कारण यह हो सकता है कि भारत की 'राष्ट्रीय आय' का उपयोग सरकारी कर्मियों की 'खपत' को पोषित करने में खप रहा है। फलस्वरूप जनकल्याण और आर्थिक विकास दोनों पीछे होते जा रहे हैं।

इसी क्रम में विश्व बैंक ने बताया है कि, वैश्विक स्तर पर सरकारी खपत में गिरावट हो रही है। वैश्विक स्तर पर 2009 में सरकारी खपत देश की कुल आय का 18.0 प्रतिशत थी जो कि 2014 में घटकर 17.2 प्रतिशत हो गई और 2019 में घटकर 17.1 प्रतिशत रह गई। तुलना में भारत में सरकारी खपत बढ़ती जा रही है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2014 में देश की आय में सरकारी खपत का हिस्सा 10.4 प्रतिशत था जो 2020 में बढ़कर 12.6 प्रतिशत हो गया है। स्पष्ट है कि, जहां वैश्विक स्तर पर सरकारी खपत में गिरावट आ रही है वहीं भारत में सरकारी खपत में तीव्र वृद्धि हो रही है। यहां यह स्पष्ट करना होगा कि, वैश्विक स्तर पर सरकारी खपत लगभग 17 प्रतिशत की तुलना में भारत में 12 प्रतिशत है। कारण यह है कि, तमाम देशों में सरकारी कर्मियों की नियुक्ति अधिक संख्या में की गई है। जैसे भारत में एक लाख नागरिकों के पीछे 139 सरकारी कर्मी हैं जबकि अमेरिका में एक लाख नागरिकों के पीछे 668 सरकारी कर्मी हैं। अमेरिका में भारत की तुलना में सरकारी कर्मियों की संख्या लगभग पांच गुना है। यानी भारत में 12.6 प्रतिशत सरकारी खपत में 139 कर्मी नियुक्त हैं तो अमेरिका में 17.1 प्रतिशत सरकारी खपत में 668 कर्मी नियुक्त हैं। अतः हमें इस बात से विचलित नहीं होना चाहिए कि, वैश्विक स्तर पर सरकारी खपत ज्यादा है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि, भारत में कम संख्या में कर्मियों द्वारा अधिक खपत क्यों की जा रही है। समस्या यह है कि, अपने देश में सरकारी खपत में वृद्धि हो रही है जबकि वैश्विक स्तर पर इसमें गिरावट आ रही है।

चिंताजनक विषय यह भी है कि, विश्व श्रम संगठन के अनुसार कोविड संकट के दौरान भारत में सभी कर्मियों के वेतन में 3.6 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि असंगठित श्रमिकों के वेतन में 22.6 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह गम्भीर है क्योंकि एक तरफ सरकार की खपत में वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ नागरिक की आय में गिरावट आ रही है। स्पष्ट है कि, भारत में सरकारी कर्मी जनता का कल्याण अथवा विकास में सहयोग देने के स्थान पर जनता का दोहन करने और विकास में गिरावट लाने की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि, सरकारी कर्मी अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करते हैं। वे कार्य करते हैं। उनमें से कई ईमानदार भी हैं। लेकिन कार्य के लिए जिस प्रकार के वेतन उन्हें दिए जा रहे हैं, उनका देश पर विपरीत प्रभाव पड़ता दिख रहा है।

राज्यों की स्थिति और भी कठिन है। केरल में सरकार का 70 प्रतिशत बजट सरकारी कर्मियों के वेतन देने में खप जाता है और तमिलनाडु में 71 प्रतिशत। तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के हेड मास्टर को 1 लाख 3 हजार रुपए प्रति माह का वेतन दिया जा रहा है जो कि निजी स्कूल में 15 हजार रुपए मात्र ही होगा। इसके बावजूद सरकारी विद्यालयों में छात्रों का रिजल्ट निजी विद्यालयों की तुलना में कमजोर ही रहता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि, सरकारी कर्मियों को अधिक वेतन देने से उनकी कार्यकुशलता में सुधार हुआ है जबकि इनकी कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए हर वेतन आयोग द्वारा कुछ संस्तुतियां की जाती हैं। इन्हें ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है और केवल वेतन वृद्धि कि संस्तुतियों को लागू कर दिया जाता है। जैसे पांचवें वेतन आयोग ने कहा था कि, क्लास 'ए' अधिकारियों का प्रति पांच वर्ष पर बाह्य मूल्यांकन कराया जाए। इस संस्तुति को ठंडे बस्ते में रख दिया गया था और सरकारी कर्मियों के वेतन में लगभग दो गुना से अधिक वृद्धि कर दी गई थी।

डॉ. भरत झुनझुनवाला
आर्थिक विशलेषक

इस परिस्थिति में सरकार को वर्तमान सरकारी कर्मियों के वेतन में कटौती करके इन्हें तर्कसंगत बनाना केवल सातवां हिस्सा कर देना चाहिए, जिससे कि ये वियतनाम और चीन के समान हो जाएं। इस बची हुई रकम से वर्तमान सरकारी कर्मियों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। वर्तमान में यदि 2 करोड़ सरकारी कर्मियों हैं तो 12 करोड़ और कर्मियों को नियुक्त कर कुल 14 करोड़ सरकारी कर्मी नियुक्त कर दिए जाएं। ऐसा करने से दो विसंगतियां दूर हो जाएंगी। पहली यह कि, हमारे सरकारी कर्मियों का वेतन दूसरे तीव्र विकास करने वाले देशों के समतुल्य हो जाएगा और दूसरा यह कि, सरकार के पास 14 करोड़ कर्मियों की एक नई फ़ौज तैयार हो जाएगी, जिससे जनकल्याण और आर्थिक विकास के कार्य संपादित हो सकेंगे।

# टोक्यो में डंका

टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनि लेखरा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा एसएच-1 में यह स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान की अवनि लेखरा ने इतिहास रच दिया। टोक्यो पैरालिंपिक में अवनि लेखरा ने फाइनल में 249.6 पॉइंट हासिल कर यूक्रेन की इरिना शेटनिक के रिकॉर्ड की बराबरी की। शूटिंग में गोल्ड जीतने के साथ ही अवनि देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई, जिसने ओलिंपिक या पैरालिंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। पुरुषों की एफ-56 डिस्कस थ्रो स्पर्धा में भारत के योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीता। जबकि पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया रजत पदक जीतने में सफल रहे। वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक पर कब्जा किया।

अब तक भारत सात पदक जीत चुका है और कई स्पर्द्धाओं में पदक पक्का कर लिया है। मगर अवनि की जीत सबसे अहम है। एक ऐसी खिलाड़ी का गोल्ड जीतना जो जीवन से हार चुकी थी और अपाहिज की तरह जीवन गुजारने के सिवाए दूसरा रास्ता नहीं था। मगर अवनि ने अपने माता-पिता के सहारे नई यात्रा शुरू की। उनकी प्रेरणा से आज ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, जिसकी खुद उन्हें उम्मीद नहीं थी। अवनि का गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं है, यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो सफलता न मिलने पर निराश हो जाते हैं या शारीरिक अक्षमता को जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढने से रुक जाते हैं। जयपुर की रहने वाली अवनि ने 9 वर्ष पहले कार एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे, अवनि व्हीलचेयर पर हैं। पैरालिंपिक इतिहास में भारत के लिए महिलाओं ने तीसरा मेडल जीता है, इससे पहले शॉटपुट में दीपा मलिक और इसी पैरालिंपिक में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में मेडल जीता है। वहीं ओलिंपिक में महिलाओं ने भारत को अब तक 8 मेडल दिलाए हैं। इनमें पीवी सिंधु ने 2, जबकि कर्णम मल्लेश्वरी, साइन नेहवाल, मैरीकॉम, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, लवलीना भारत को मेडल दिला चुकी हैं। हालांकि कोई भी महिला आज तक भारत को गोल्ड नहीं दिला पाई।

टोक्यो पैरालंपिक में कामयाबी की नई इबारत लिखने वाली अवनि ने 2015 में जयपुर (राजस्थान) के जगतपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शूटिंग शुरू की। 8 नवंबर 2001 को जयपुर में जन्मी अवनि को पिता ने खेल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। अवनि ने शुरू में शूटिंग और तीरंदाजी दोनों की कोशिश की। इसके बाद अवनि को शूटिंग में ज्यादा मजा आया। इसके बाद वह इसे ही जारी रखा। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की किताब पढने के बाद वह और भी प्रेरित हुई। बता दें कि, अवनि राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की हैं। अवनि ने 2017 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। यूएई में हुए विश्व कप में उन्होंने हिस्सा लिया था। 2019 में उन्हें भारत में गोस्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा मोस्ट प्रॉमिसिंग पैरालंपिक एथलीट नामित किया गया था। अवनि ने 2018 में एशियन पैरा गेम्स में भी हिस्सा लिया था। इससे पहले टोक्या ओलंपिक भी भारत के लिहाज से काफी उम्दा रहा था। उत्साहजनक और संतोषजनक केवल यह नहीं है कि, टोक्यो गए हमारे अनेक खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे उतरे, बल्कि यह भी है कि वे देश में एक नई खेल संस्कृति विकसित हो जाने की गवाही भी दे रहे हैं। भले ही अपने प्रदर्शन से देश-दुनिया का ध्यान खींचने वाले कुछ खिलाड़ी पदक तालिका में अपना नाम अंकित न कर सके हों, लेकिन वे अपनी हिम्मत और कौशल से बेहतर भविष्य की मुनादी कर रहे हैं। यह नतीजा है उस नई खेल संस्कृति का, जो हाल के वर्षों में विकसित की गई और जिसके तहत खिलाडियों को कहीं बेहतर सुविधाओं के साथ समुचित प्रशिक्षण दिया गया। जहां कुछ खिलाडियों को विदेशी प्रशिक्षक उपलब्ध कराए गए, वहीं कुछ को विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेश भी भेजा गया। यह सब इसीलिए हो पाया, क्योंकि खेल संघों पर काबिज तमाम ऐसे लोगों को किनारे कर पेशेवर व्यक्तियों को लाया गया, जो उन्हें अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इसके चलते खेल और खिलाडियों को वह प्राथमिकता नहीं मिल पाती थी, जो जरूरी थी। टोक्यो ओलिंपिक के समापन के वक्त भारत की झोली में चाहे जितने ज्यादा पदक हों, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि खेल एवं खिलाडियों को और अच्छे से विकसित करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

सिद्धार्थ शंकर

# शीघ्र कार्रवाई को लेकर कोर्ट सख्त

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि, उच्च न्यायालय की मंजूरी के बगैर सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले वापस नहीं लिए जा सकते। यह आदेश निश्चित ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार के लिए एक शुभ संकेत है, लेकिन इससे आपराधिक छवि वाले नेताओं को चुनाव लड़कर संसद या विधानमंडल में पहुंचने से रोकना संभव नहीं है।

आपराधिक छवि वाले नेताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले वापस लेने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना जरूरी है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जघन्य अपराधों के साथ ही सफेदपोश अपराधों के आरोपी नेताओं को चुनाव प्रक्रिया से बाहर करने के लिए जरूरी है कि, इनके खिलाफ मुकदमों पर तेजी से निर्णय सुनाया जाए क्योंकि अदालत द्वारा दो वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलने की स्थिति में वे स्वतः ही जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों को निर्वाचित होकर संसद या विधानमंडल में पहुंचने से रोकने के लिए राजनीतिक दलों, पुलिस-प्रशासन और आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों के गठजोड़ को तोड़ना बहुत जरूरी है। इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए जांच एजेन्सियों को किसी भी तरह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव से मुक्त कराना होगा। सुनिश्चित हो कि, आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज मामलों की तेजी से जांच करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जाए और निचली अदालतें तेजी से इन पर सुनवाई करके अपने फैसले सुनाएं।

दरअसल, आपराधिक मामलों में इन माननीय नेताओं के खिलाफ जांच ही पूरी नहीं होती। जांच पूरी नहीं होती है तो आरोप पत्र दाखिल नहीं होते हैं। आरोप पत्र दाखिल नहीं होता है तो मुकदमा चलाने के लिए अभियोग निर्धारित नहीं हो सकते और ऐसे मुकदमे अधर में ही लटके रहते हैं। उच्चतम न्यायालय की मंशा है कि, आपराधिक छवि वाले इन नेताओं के खिलाफ लंबित मुकदमों के तेजी से निपटारे हों। न्यायालय के सख्त रुख के बाद केन्द्र सरकार ने इन नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित कीं लेकिन इसके बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इसकी वजह जांच एजेंसियों के कामकाज में सत्तारूढ़ दलों की ओर से पड़ने वाला कथित दबाव और पर्याप्त संख्या में इन एजेंसियों के पास स्टाफ का नहीं होना भी है।

सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई में विलंब की एक वजह अचानक ही संबंधित अदालत के न्यायाधीश का तबादला भी होती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि, सांसदों और विधायकों के विरुद्ध मामले की सुनवाई कर रहे विशेष अदालतों के न्यायाधीशों का अगले आदेश तक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति और मौत जैसे अपवादों में यह आदेश लागू नहीं होगा।

यह सही है कि, विशेष अदालतें नेताओं से संबंधित मुकदमों की सुनवाई कर रही हैं लेकिन इनकी रफ्तार अपेक्षित नहीं है। किसी न किसी वजह से इन अदालतों में सुनवाई स्थगित होती रहती है। यह स्थिति तब है जब शीर्ष अदालत कह चुकी है कि, विशेष अदालतें सांसदों और विधायकों से संबंधित उन आपराधिक मुकदमों को प्राथमिकता दें, जिनमें अपराध के लिए उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है।

यही नहीं, न्यायालय ने तो 16वीं लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले मार्च, 2014 में एक आदेश में कहा था कि, जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (1), धारा 8 (2) और धारा 8 (3) के दायरे में आने वाले अपराधों में मुकदमे का सामना कर रहे सांसदों और विधायकों के मामले, जिनमें आरोप निर्धारित हो चुके हैं, यथासंभव एक साल के भीतर सुनवाई पूरी की जाए। यदि किसी वजह से ऐसे मुकदमे की सुनवाई एक वर्ष के भीतर पूरी नहीं होती है तो विशेष अदालत को इसके कारणों के साथ उच्च न्यायालय को स्पष्टीकरण देना था। इसके बावजूद नेताओं के खिलाफ गंभीर अपराधों के मुकदमों की सुनवाई अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी। स्थिति की गंभीरता का अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि डाकेजनी, अपहरण, जबरन वसूली, बलात्कार, बलात्कार के प्रयास, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे अपराधों से इतर बड़ी संख्या में सांसद और विधायक सफेदपोश अपराध के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं।

अनुप भटनागर

यह विडंबना ही है कि, इस समय 51 पीठासीन और पूर्व सांसदों सहित 120 से ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ धनशोधन के आरोपों की प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है जबकि 121 अन्य ऐसे ही माननीयों के खिलाफ तरह-तरह के अपराध के आरोपों में सीबीआई ने भी मामले दर्ज कर रखे हैं। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने चिंता व्यक्त की और कहा कि, प्रवर्तन निदेशालय के पास 76 मामले 2012 से लंबित हैं जबकि सीबीआई के पास 2000 से 58 मामले लंबित हैं। यह अपने आप में सारी स्थिति बयां कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि, सत्तारूढ़ दल और नौकरशाही भी स्थिति में बदलाव नहीं करना चाहते। सत्तारूढ़ दलों में अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति होती तो निश्चित ही वे दूसरी मदों पर धन व्यय करने की बजाए अदालतों और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देते। न्यायपालिका को ही यह सुनिश्चित कराना होगा कि, जांच एजेंसियां निर्धारित समय के भीतर जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल करें और विशेष अदालतों में किसी भी कीमत पर सुनवाई टाली नहीं जाये।

# मोबाइल तंत्र में ज्ञान का लोकतंत्र

ऑनलाइन शापिंग वेबसाइट अभी कुछ दिन पहले ग्रीष्म सेल चला रही थी। मोबाइल ले लो, फिर मानसून सेल में भी उसने यही कहा कि मोबाइल ले लो। फिर स्वतंत्रता दिवस की सेल पर भी यही कहा कि मोबाइल ले लो। फिर गणेश उत्सव की सेल में भी वह शापिंग वेबसाइट यह बताएगी कि मोबाइल लीजिए, एकदम खास आपके लिए। फिर दीवाली सेल पर तो उसे यह बताना ही है कि, मोबाइल लेना तो आपका कर्तव्य है।

मोबाइल के इतने आफर आस-पास टहल रहे हैं कि, मुझे फील हो रहा है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोबाइल खरीदना ही है। मोबाइल खरीदना ही नहीं, बल्कि बार-बार लगातार मोबाइल खरीदना ही उद्देश्य है। अभी एक कंपनी ने मोबाइल लांच किया, जिसे मोड़ा जा सकता है, करीब डेढ़ लाख का मोबाइल। यह बात मैंने मोबाइल के एक सेल्समैन से कही कि, डेढ़ लाख में तो एक जमाने में शादी हो जाया करती थी। उसने मुझे बताया, मोबाइल और शादी में समानता यह है कि दोनों में सुनने का इंतजाम होता है। पर मोबाइल में दो राहतें हैं, एक तो आप इसे साइलेंट कर सकते हैं, दूसरा यह कि डेढ़-दो वर्ष में यह निपट लेता है।

उसका आशय यह था कि, डेढ़ लाख में ले लीजिए, राहत रहेगी। स्पेशल मोबाइल है, इसे मोड़ सकते हैं। एक मोबाइल आया था लाख से ऊपर का, उसमें बताया गया था कि कतई चिरकुट टाइप लोगों की सेल्फी भी इसमें बहुत ही स्मार्ट आती है। बंदे में स्मार्टनेस न हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, महंगा स्मार्टफोन खरीदने की क्षमता है तो हर कोई स्मार्ट दिख सकता है। पर भाई कितना स्मार्ट दिखें, हर महीने नई स्मार्टनेस के चक्कर में नया फोन ही खरीदते रहें।

मोबाइल सेल्समैन ने जवाब दिया, क्या हर्ज है हर महीने खरीदिए। मुड़ने वाले फोन से फोटो खींचिए, बीस कैमरे वाले फोन से खींचिए सेल्फी, बस खरीदिए। मोबाइल प्रधान विश्व कर रखा। अजब हाल है, किसी से मिलने जाइए, उस घर में छोटे बच्चे हों, तो वो सबसे पहले मोबाइल पकड़ते हैं और मोबाइल पर लग जाते हैं। बड़े मोबाइल की बातें करते हैं, मोबाइल के मॉडलों की बात करते हैं। मोबाइल की बातें हैं, मोबाइल पर बातें हैं। खबर मोबाइल पर, मैसेज मोबाइल पर, मोबाइल से बाहर कोई दुनिया भी है, ऐसा नई पीढ़ी के कई लोगों को पता नहीं है।

आलोक पुराणिक

मोबाइल पर ही शोक संवेदना, मोबाइल पर ही खुशी का इजहार, पर बंदा निपट ले तो उसे निपटाने के लिए ऑफलाइन श्मशान घाट ही ले जाना पड़ता है। वहां मामला ऑनलाइन नहीं हो सकता, यह मोबाइल की सीमा है। वरना कोई कंपनी इस तरह का सॉफ्टवेयर ले आती कि डेड बॉडी को स्कैन करें, अपने आप हमारा सॉफ्टवेयर उसे निपटा देगा। सबको मोबाइल ही निपटाएगा, बल्कि निपटा ही रहा है। सुबह से शाम तक मोबाइल से हासिल ज्ञान से कोई भी बड़े-बड़े प्रोफेसरों को निपटा देता है। बड़े-बड़े विद्वान व्हाट्सएप पर बरस रहे ज्ञान के आगे धराशाई हो जाते हैं। हजार मोबाइलों पर व्हाट्सएप ज्ञान के आगे एक प्रोफेसर की एक किताब हार जाती है। यह ज्ञान का लोकतंत्र है, जिसका मैसेज ज्यादा शेयर हो गया, वह ज्ञानी।

# प्रदेश में अब सुनाई देगी अफ्रीकन चीतों की दहाड़

**माही की गूंज, मंदसौर।**

श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से 20 चीते नंवबर या दिसंबर के पहले सप्ताह में लाए जाएंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चीतों को भारत लाने की तैयारी को लेकर केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से चर्चा की। यादव ने बताया, केंद्र सरकार की कोशिश है कि दो चरणों में 10 नर और 10 मादा चीते कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट करा दिए जाएंगे।

जानकारी के मुताबिक चीता को फिर से देश में लाने के लिए लंबे समय से प्रोजेक्ट चल रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को इसकी मंजूरी दी है। प्रयोग के लिए अफ्रीकन चीते को भारत के जंगलों में लाया जाए। पिछले कुछ महीनों से प्रोजेक्ट ने फिर रफ्तार पकड़ी है।

### 5 वर्ष में 75 करोड़ खर्च होंगे

वन विभाग के अनुसार नवंबर-दिसंबर में 20 अफ्रीकी चीते भाजर आएंगे। दक्षिण अफ्रीका से ये चीते ग्वालियर पहुंचेंगे। यहां से सड़क मार्ग के जरिए इन्हें कूनो राष्ट्रीय पार्क ले जाया जाएगा। वन मंत्री विजय शाह ने बताया कि, कूनो राष्ट्रीय उद्यान चीता बहाली परियोजना पर जागरूकता बढ़ाने के 5 वर्ष में 20 चीतों के रख-रखाव पर करीब 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पेट्रोलियम कंपनियों की मदद से वन विभाग ने इसे अरेंज किया है।

### हुआ था सर्वे

मार्च 2021 में एक्सपर्ट की टीम ने कूनो राष्ट्रीय पार्क का सर्वेक्षण किया था। उन्होंने रिपोर्ट में कहा था कि, चीताओं को यहां रखा जा सकता है। कूनो पार्क को इस हिसाब से तैयार किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रोजेक्ट पर जनवरी महीने में मीटिंग की थी। कूनो राष्ट्रीय पार्क 750 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बीच में सिर्फएक गांव आता है, इसको भी कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है।

### नौरादेही अभयारण को भी माना गया था अनुकूल

कूनो के अलावा 1 हजार 200 किलोमीटर में फैले नौरादेही अभयारण को भी चीतों के लिए अनुकूल माना गया था, लेकिन कूनो को ज्यादा अनुकूल माना गया। राजस्थान में चीतों के लिए गांधी सागर-चितौडगढ़-

भैंसरोदगढ़ अभ्यारण का भी सर्वेक्षण किया गया था। कूनो को पहले गिर से शेर लाने के लिए भी चुना गया था।

माधव नेशनल पार्क में टाइगर की पुनः बसाहट

इसके साथ ही शिवपुरी स्थित माधव नेशनल पार्क में टाइगर की पुनः बसाहट के सिंधिया के प्रस्ताव पर यादव ने इस संबंध में अधिकारी को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए। केंद्र एवं राज्य सरकार का एक दल प्रस्ताव के अध्ययन के लिए माधव नेशनल पार्क का दौरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सिंधिया ने इको वाइल्ड लाइफपर्यटन को मध्य प्रदेश व देश के अन्य क्षेत्रों में विश्व के अन्य क्षेत्रों की तरह कैसे विकसित किया जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा की।

# गांधी सागर अभ्यारण में मिला संजीवनी बूटी का पौधा

**माही की गूंज, मंदसौर।**

जिले के गांधी सागर अभयारण्य में वनस्पति विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज खान (रिसर्च स्कॉलर, महाराजा श्री राम चंद्र भांजा भांजा देव विश्वविद्यालय ओडिसा) एवं सुभद्रा बारिक ने 6 लोगों की टीम के साथ वनस्पति व जड़ी बुडिय पौधों का सर्वे किया। जिसमें श्रीराम के अनुज लक्ष्मण जी के प्राण बचाने वाली संजीवनी ÷अग्निशिखा÷ का पौधा मिला है। संजीवनी बूटी 'अग्निशिखा' यानी विषलया का पौधा भी मिला है।

धार्मिक मान्यता है कि, रामायण काल में लक्ष्मण के प्राण बचाने में इस औषधि का उपयोग किया गया था। अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध गांधी सागर अभयारण्य में पहली बार वनस्पतियों का सर्वे हुआ। जिसमें 502 से अधिक प्रजातियां मिली है। जिनमें से 300 से अधिक औषधीय हैं और 70 प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त मानी जाने वाली है। इसके अतिरिक्त ब्रीमेक प्लांट, दूधी, निर्गुंडी, गुरमार भी पाए गए हैं। वही इस सर्वे से पहले वन विभाग के पास गांधीनगर में केवल 48 पेड़ पौधों की प्रजातियों का ही डाटा था।

डॉ. परवेज खान ने बताया कि, गांधी सागर अभयारण्य में कई औषधीय पौधों में मूल्यवान रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि बहुत उपयोगी हैं। यहां विस्तृत अध्ययन की जरूरत है औषधीय प्रजातियों का एक उचित दस्तावेज होना और स्वास्थ्य व स्वच्छता में सुधार के लिए उनकी क्षमता को जानना जरूरी है।

## पूर्व विधायक की जयंती पर किया पौधरोपण

**माही की गूंज, भानपुरा (मंदसौर)।**

गरोठ विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय राजेश यादव की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर गरोठ भानपुरा विधानसभा के लोगों द्वारा पौधरोपण किया गया। स्वर्गीय राजेश यादव मित्र मंडल के आह्वान पर राजेश यादव की जन्म जयंती पर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए आग्रह किया गया था, जिसके बाद गरोठ भानपुरा कि कई पंचायतों में, गांव मे, वार्ड में धार्मिक स्थलों पर स्कूल परिसर, अस्पताल परिसर, खेल ग्राउंड आदि अनेक जगहों पर हजारों की तादाद में स्वर्गीय राजेश यादव के समर्थकों ने पौधे रोपे गए। पूर्व विधायक स्वर्गीय राजेश यादव क्षेत्र के एक ऐसे विधायक रहे हैं जिनका सीधा जुड़ाव विधानसभा के हर एक व्यक्ति से था, जिसको लेकर आज भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ कई समाजसेवी, गणमान्य नागरिक व गैर राजनीतिक लोगों द्वारा भी पौधारोपण कर राजेश यादव को याद किया गया।

विनीत राजेश यादव ने स्वर्गीय विधायक राजेश यादव की जन्म जयंती पर हजारों की संख्या में पौधे रोपने पर सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है।

## मार्च के बाद हुए मृत व्यक्तियों का डाटा एकत्रित करने के कलेक्टर ने दिए आदेश

**माही की गूंज, शाजापुर।**

जिले में मार्च 2021 के बाद मृत होने वाले व्यक्तियों का डाटा एकत्रित करने के आदेश कलेक्टर ने दिए। समयसीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर दिनेश जैन ने उक्त आदेश जारी कर सामाजिक न्याय विभाग की प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर सुश्री प्रियंका वर्मा को दायित्व दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती मिशा सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि, मार्च 2021 के बाद परिवार के मुखिया उर्फकमाउ सदस्य की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को पात्रतानुसार शासन की योजनाओं से लाभांवित करने के लिए मृत व्यक्तियों का डाटा होना जरूरी है। कलेक्टर ने खाद्य विभाग, नगरपालिका सीएमओ, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि, मृत होने वाले व्यक्तियों के परिजनों को पात्रतानुसार शासन की योजनाओं से लाभांवित करें। समयसीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने उपसंचालक पशु चिकित्सा को निर्देश दिए कि, किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के कार्य में प्रगति लाएं। साथ ही विभागीय योजनाओं के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की लंबित देनदारियों का भुगतान कराएं। कृषि उपसंचालक को निर्देश दिए कि, जिले में काले गेंहू का उत्पादन बढ़ाने एवं उनके उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए डाटा एकत्रित करें। महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाएं। ऐसी आंगनवाड़ी केन्द्र जिनका स्वयं का भवन नहीं है और किराए के भवन में संचालित हो रही है, उन्हें निकटस्थ विद्यालय में शिफ्ट कराएं। साथ ही नए आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण के लिए प्रस्ताव भी भेजें। रोजगार अधिकारी रोजगार मेलों का आयोजन कराएं। साथ ही जिन लोगों का चयन हुआ है उन्हें जाँब आफर मिला है कि नहीं यह भी देखें। योजना अधिकारी विधायक एवं सांसद क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित करें। आपूर्ति अधिकारी जिले में पीएनजी एवं सीएनजी स्टेशन स्थापित करने के लिए कार्रवाई करें।

## आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी गति पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी

**माही की गूंज, रतलाम।** शहर में आयुष्मान कार्ड निर्माण की गति धीमी होने पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर द्वारा निगम आयुक्त तथा एसडीएम को निर्देश दिए गए कि, आयुष्मान कार्ड निर्माण की गति बढ़ाई जाए। शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ समयावधि में हितग्राहियों को मिले।

कलेक्टर द्वारा जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन को भी निर्देशित किया गया कि, जिला चिकित्सालय की ओपीडी में आने वाले मरीजों में से पात्र हितग्राहियों का चयन करके उनके कार्ड बनाए जाएं। कलेक्टर सुश्री शिराली जैन को निर्देश दिया कि, वह प्रतिदिन आयुष्मान कार्ड निर्माण की मानिटरिंग करें। सभी एसडीएम को एक हजार कार्ड प्रतिदिन बनाने के लिए निर्देशित किया। बैठक में जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षी सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम एमएल आर्य, अभिषेक गहलोत आदि उपस्थित थे।

## तीन आरोपियों को किया जिला बदर

**माही की गूंज, शाजापुर।** जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दिनेश जैन ने अपराधिक गतिविधियों में लिप्त तीन आरोपियों को 3 माह के लिए जिला बदर किया है। थाना कोतवाली शाजापुर छापीहेड़ा निवासी प्रेमसिंह पिता रामसिंह राजपूत (38), बेरछा थाना बेरछा मंडी निवासी शानू उर्फआशिक उर्फआरिफ पिता फेजुल्ला (21) तथा थाना मक्सी ग्राम सिरोलिया निवासी प्रेमसिंह पिता बलदेवसिंह (40) को तीन माह के लिए जिला बदर करते हुए शाजापुर एवं सीमावर्ती जिले देवास, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़ तथा सीहोर की राजस्व सीमा से बाहर जाने के आदेश जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए है।

## भौतिक घरेलु सुख-सुविधा संपन्न परिवार को नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ

**माही की गूंज, रतलाम।**

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के अंतर्गत जिले के छूटे हितग्राहियों को सितंबर माह में कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आयोजित बैठक में योजना क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों तथा गैस एजेंसियों को निर्देशित किया कि, शेष हितग्राहियों के लिए अभियान संचालित कर कनेक्शन प्रदान किए जाएं। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी एसएच चौधरी, सहायक आपूर्ति अधिकारी उमेश पांडे तथा गैस एजेंसियों के संचालक उपस्थित थे।

बैठक में बताया कि, योजना में हितग्राही को तीन पासपोर्ट फोटो, पहचान प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, सभी के आधार नम्बर, वरिष्ठ महिला मुखिया का खाता, राशन कार्ड अथवा समग्र आईडी तथा मोबाइल नंबर, शासकीय उचित मूल्य दुकान या ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करना होगा। जो पात्र नहीं होकर गरीब परिवार से संबंध रखते हैं उन्हें दावे के रूप में 14 बिंदुओं का घोषणा पत्र देना होगा। परिवार के किसी सदस्य की 10 हजार रुपए से ज्यादा आय हो, आयकरदाता हो, प्रोफेशनल टैक्स चुकाते हो, घर में रेफ्रिजरेटर होने, परिवार में सरकारी कर्मचारी हो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर होने पर उसे योजना में कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि, पंचायत स्तर पर पात्र हितग्राहियों के केवाईसी फॉर्म भरवाने के लिए शिविरों का आयोजन करें। शिविरों में राजस्व, खाद्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा सहयोग दिया जाएगा।

जिला आपूर्ति अधिकारी चौधरी ने बताया कि, योजना के तहत जिले में 86 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की जा चुकी है, मात्र 12 हजार गैस कनेक्शन और प्रदाय किया जाना है।

## गौवंश परिवहन में प्रयुक्त वाहन को किया अधिहरण

**माही की गूंज, शाजापुर।** कलेक्टर दिनेश जैन ने गौवंश का अवैध परिवहन करने पर जप्तशुदा लोडिंग पिकअप वाहन क्रमांक आरजे 17 जीए 5963 को अधिहरण करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिला परिवहन अधिकारी को आदेशित किया है कि, वे अपिलीय अवधि 30 दिवस व्यतित होने के पश्चात् अधिहरण किए लोडिंग वाहन को पुलिस थाना सुनेरा से प्राप्त कर नीलामी की कार्रवाई करें और नीलामी से प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा कराएं।

उल्लेखनीय है कि, विगत 24 मार्च 2019 को थाना सुनेरा ने मुखबीरी सूचना के आधार पर लोडिंग पिकअप वाहन क्रमांक आजे 17 जीए 5963 को गौवंश को ठूस-ठूस कर करूरता पूर्वक भरकर अवैध रूप से परिवहन करने पर जप्त कर प्रकरण दर्ज किया था।

## जनमाष्टमी पर परिवहन मंत्री ने मंदिर ट्रस्ट को दी सहायता

**माही की गूंज, शाजापुर।**

राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर में श्री गोवर्धन मंदिर पहुँचकर यादव समुदाय द्वारा आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव में भगवान श्रीकृष्ण का पूजन किया और उपस्थित जन-समुदाय को शुभकामनाएं दीं। जन्मोत्सव की बधाई लेते हुए श्री राजपुत ने कहा कि, मेरा नाम भी गोविंद शायद इसीलिए रखा गया कि मेरा जन्म भी जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इस अवसर पर उन्होंने श्री गोवर्धन मंदिर ट्रस्ट को 5 लाख रूपए की राशि मंदिर के सौन्दर्यीकरण के लिए भेंट स्वरूप प्रदान की।

### बच्चों को बांटे फल व खिलौने

श्री राजपूत जन्मदिन के अवसर पर घरौंदा आश्रम पहुँचे जहाँ उन्होंने बच्चों को फल मिठाईयाँ, खिलौने तथा चॉकलेट वितरित किया। श्री राजपूत का जन्मदिन बुंदेली परंपरा से मनाया गया। मंत्री श्री राजपूत ने उन सभी लागों के प्रति आभार माना।

## वायरल वीडियो की हुई पुष्टी, बताए गए कुछ आरोपियों का घटना से संबंध नहीं

**माही की गूंज, शाजापुर।**

सोशल मीडिया पर 25 अगस्त को ग्राम सारसी में फरियादी पक्ष को जूते-चप्पलों से मारपीट करने संबंधी वायरल हुए वीडियो की एसडीओपी ने पुष्टि करते हुए बताया है कि, वीडियो तो सही है, किन्तु फरियादियों द्वारा 28 अगस्त को एजेके थाने में दिए गए आवेदन में बच्चन पिता विष्णुप्रसाद व विष्णु गोसाई एवं इंदरसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी सारसी के नाम दिए गए हैं का उक्त घटना से कोई संबंध नहीं है। वीडियो में इनकी उपस्थिति भी नहीं है और 26 अगस्त को फरियादियों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में भी इनके नाम नहीं है।

घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 11 अगस्त को फरियादी बाबुलाल निवासी ग्राम सारसी ने उसकी 16 वर्षीय पुत्री के कहीं चले जाने की रिपोर्ट 12 अगस्त को लालघाटी थाने में दर्ज कराई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना कर आरोपी अर्जुन पिता अमरसिंह निवासी ग्राम सुनवानी गोपाल थाना विजयगंज मंडी जिला देवास को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण के अनुसार आरोपी अर्जुन के रिश्तेदार मानुलाल पिता किशनलाल व बंशीलाल पिता सिद्धुजी निवासी ग्राम टांडाबोल्डी विगत 25 अगस्त को ग्राम सारसी अपने रिश्तेदार से मिलने गए थे। यहां उनके साथ मारपीट हुई, जिसकी एफआईआर 26 अगस्त को मानुलाल एवं बंशीलाल ने कराई थी। जिसमें उनके स्वजातीय व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने का उल्लेख है। 28 अगस्त को इनके द्वारा पुनः आवेदन देकर बताया कि, मारपीट के दौरान स्वजातीय व्यक्तियों के साथ बच्चन पिता विष्णुप्रसाद, विष्णु गोसाई, इंदरसिंह पिता देवीसिंह राजपूत ने भी मारपीट की और जूतों का हार पहनाकर जुलूस निकाला।

प्रकरण में एसडीओपी ने बताया कि, वीडियो की पुष्टि हुई है, किन्तु इसमें उक्त व्यक्तियों का घटना से संबंध होना नहीं पाया गया।

## राज्यपाल ने 130 नवीन पाठ्यक्रमों का किया शुभारंभ

**इंदौर।** राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने गत दिवस विक्रम कीर्ति मन्दिर में विक्रम विश्वविद्यालय के 130 नवीन पाठ्यक्रमों का शुभारम्भ किया। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि, विश्वविद्यालय में एक साथ 130 से अधिक नवीन पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। इन्हें मिलाकर अब कुल 180 पाठ्यक्रम हो जाएंगे। नवीन पाठ्यक्रम युवाओं को भविष्य में नवीन ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। नवीन पाठ्यक्रम युवाओं को एक ही विषय में बंधे रहने से मुक्त कराएगा और आगे बढ़ने में मदद कर आत्म-निर्भर बनाएगा। राज्यपाल ने कहा कि, विश्वविद्यालय को संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हम सब प्रयास करें कि भारत पुनः विश्वगुरू कहलाए।

राज्यपाल श्री पटेल ने सभी लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जयिनी रही है। उज्जयिनी की पावन एवं पवित्र नगरी में आने से मेरा मन गर्व का अनुभव कर रहा है। उज्जयिनी नगरी प्राचीनकाल से ही पवित्र नगरी रही है। यहाँ के लोगों का सौभाग्य है कि, स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने यहाँ गुरू सान्दीपनि के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण की। उस समय राज परिवार एवं सामान्य बालक सब एक साथ गुरूकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। भगवान श्रीकृष्ण एवं सुदामा ने साथ ही गुरू सान्दीपनि के आचार्यत्व में शिक्षा ग्रहण की। भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कर्त्तव्य पालन की सीख दी। श्री पटेल ने कहा कि विक्रम विश्वविद्यालय में पढ़कर अनेक विद्यार्थी निकले हैं, जिन्होंने जीवन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए हैं।

राज्यपाल श्री पटेल ने कार्यक्रम से पूर्व सम्राट विक्रमादित्य की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नृत्य-संगीत के कलाकारों ने पारम्परिक नृत्य कर राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल श्री पटेल को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अखिलेश कुमार पाण्डेय ने विश्वविद्यालय की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। संचालन प्रो. शैलेंद्र कुमार शर्मा एवं आभार प्रदर्शन कुलसचिव डॉ. प्रशांत पौराणिक ने किया।

समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्री विजय कुमार, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य, विश्वविद्यालय विनायम आयोग के सदस्य, ओम जैन, संभागायुक्त संदीप यादव, एडीजी योगेश देशमुख, कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येन्द्र कुमार शुक्ला आदि मौजूद थे।

## न्यूज ब्रीफ

### घर में घुस कर मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष की कैद

**माही की गूंज, बड़वानी।** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका गिरी शर्मा ने पारित अपने फैसले में घर में घुसकर मारपीट करने के आरोपी नन्नु उर्फ नरेन्द्र पिता घीसा को धारा 452 मे एक वर्ष का कारावास व धारा 323 में 6 माह का कारावास से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु कीर्ति चैहान द्वारा की गई।

### फरार आरोपी पर 4 हजार रुपए का इनाम घोषित

माही की गूंज, बड़वानी। पुलिस अधीक्षक बड़वानी निमिष अग्रवाल ने सेंधवा थाने में आबकारी एक्ट में दर्ज प्रकरण में फरार दानोद के रहवासी भागीरथ पिता बंशीलाल वास्कले पर 4 हजार रूपए का इनाम घोषित किया है। यह इनाम उक्त आरोपी का पता देने वाले या इसको गिरफ्तार करवाने वाले को मिलेगा। सूचना देने वाले का नाम सर्वथा गोपनीय रखा जाएगा ।

### कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ में करंट इवेंट्स का बताया महत्व

**माही की गूंज, बड़वानी।** प्राचार्य डॉ. एनएल गुप्ता के मार्गदर्शन में संचालित शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कॅरियर उन्नयन करने के संबंध में इंटरनेट के माध्यम से करंट इवेंट्स का महत्व बताया।

पुस्तकालय विशेषज्ञ कार्यकर्ता प्रीति गुलवानिया ने बताया कि, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र में करंट इवेंट्स पर आधारित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट इवेंट्स पर कमांड किए बिना प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है।

डॉ. मधुसूदन चैबे ने कहा कि, करंट इवेंट्स पर पकड़ बनाने के लिए प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्रीय स्तर के एवं एक राज्य स्तर के समाचार पत्र को पढ़कर महत्वपूर्ण घटनाओं के नोट्स बनायें तथा उनका नियमित अंतराल से रिवीजन करें। आकाशवाणी, दूरदर्शन और बीबीसी के समाचार बुलेटिन भी उपयोगी हैं। करंट इवेंट्स पर आधारित मासिक पत्रिकाएं भी अध्ययन हेतु उपलब्ध हैं, उनका भी लाभ लें।

### आशा कार्यकर्ताओं ने घर-घर पहुंचकर किया लार्वा सर्वे

**माही की गूंज, बड़वानी।** जिले में चल रहे लार्वा सर्वे अभियान के तहत आशा कार्यकर्ताओं का घर-घर पहुंचकर लार्वा सर्वे का कार्य चल रहा है। इसके तहत नगरीय क्षेत्रों एवं बड़े कस्बों में आशा कार्यकर्ता जहां घरों पर पहुंचकर लोगों को मच्छर जनित रोगों के प्रति जागरूक कर रही है। वही उन्हे बचाव के तरीके से भी अवगत करा रही है। इस दौरान आशा कार्यकर्ता घरों में संग्रहित पानी की टंकियों की भी जांच कर लार्वा पाये जाने पर जहां पानी को अपने समक्ष खाली करवा रही है। वही पानी में क्लोरिन एवं ब्लीचिंग में समक्ष डलवा रही है।

जिला मलेरिया अधिकारी वसीम शेख से प्राप्त जानकारी अनुसार बुधवार को भी जिले के राजपुर, सेंधवा, बलवाड़ी में यह सर्वे का कार्य आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है।

### प्रतिमाओं के निर्माण में पीओपी का उपयोग करना प्रतिबंधित

**माही की गूंज, खरगोन।** अपर कलेक्टर बीएस सोलंकी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आगामी धार्मिक त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण जिले में मूर्तियों एव झॉकियों के निर्माण में प्लॉस्टर ऑफपैरिस (पीओपी) का उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई निर्माता या विक्रेता के पास प्लॉस्टर ऑफपैरिस से बनी मूर्तिया या मूर्तिया निर्माण करते हुए पाया जाता है या आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। मूर्तियों का निर्माण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर जारी आदेश अनुसार किया जाएगा।

### मयूरी शर्मा होंगी चन्द्रशेखर आज़ाद नगर की नई सीएमओ

**माही की गूंज, अलीराजपुर।** मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद चन्द्रशेखर आज़ाद नगर इकबाल हुसैन मनिहार को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना संवाद कार्यक्रम के दौरान व्यवस्थाओं में कोताही बरतने पर कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने निलंबित कर दिया। सिविल सेवा अधिनियम 1966 के तहत उक्त कार्रवाई की गई थी। वही मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी ट्रांसफर सूची में मयूरी शर्मा को नगर परिषद पीथमपुर जिला धार से चन्द्रशेखर आज़ाद नगर परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

# कोरोना काल में अवसर को तलाश रही खवासा की मिशनरी स्कूल....

## सेवा के नाम पर बड़ी फीस वसूलने वाली मिशनरी स्कूल ने कमीशन की लालच में पेटलावद बुक्स सेलर से किया संपर्क, बच्चों के साथ पालक भी हो रहे परेशान

**माही की गूंज, खवासा (झाबुआ)।**

मिशनरी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सेवा के नाम पर कार्य कर क्षेत्र में अच्छी स्कूल के साथ उच्च शिक्षा देने के नाम पर खवासा में संत तेरेसा स्कूल के नाम से संस्था खोली गई। उक्त संस्था की शुरुआत ही स्थानीय राजवाड़े से शुरुआत कर जिला शिक्षा अधिकारी को दिए परमिशन हेतू आवेदन को ही आमजन को शासकीय परमिशन बताकर स्कूल का संचालन शुरू किया। अपनी नीव स्वार्थ व फर्जीवाड़े के साथ शुरुआत की। तय है यह संस्था जिसने खवासा में अपनी नीव ही इस तरह से रखी जिससे सेवा भाव व उच्च शिक्षा की परिकल्पना करना शायद बेमानी होगी।

जहां कोरोना काल के चलते 2 वर्ष से स्कूल संस्थान पूरी तरह से बंद थे। वहीं सरकार ने पूरे एतीहात व बच्चे व पालक को बिना किसी परेशानी के शासकीय गाईडलाइन के अनुसार कक्षा 6 से स्कूल खोलने के आदेश एक सितंबर से जारी किए हैं। उक्त आदेश के साथ ही खवासा की संत तेरेसा स्कूल की नवयुक्त प्राचार्य ने अपने स्वार्थ को महत्व देकर शासकीय गार्डलाइन का उल्लंघन किया। स्थानीय स्तर पर ही बड़े बुक्स सेलर होने के बावजूद खवासा से 16 किलोमीटर दूर दूसरी तहसील पेटलावद के रूपांकन प्रिंटर्स एंड स्टेशनरी से सांठ-गांठ की। वहीं कोर्स लेने के लिए बच्चों एवं पालको को पेटलावद जाकर खरीदने के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है, जो स्थानीय एवं क्षेत्र के पालको को रास नहीं आ रहा है जिन्हें कई दिक्कतों का सामना करने को मजबूर होना पड़ेगा।

उक्त संत तेरेसा की स्वार्थ रूपी कारस्तानी के साथ बच्चों व पालकों को कर रहे परेशान।

वही पालक दिनेश पाटीदार के साथ कई पालको ने चर्चा कर माही की गूंज को समस्या बताई कि, जहां कोरोना काल में सर्वप्रथम आवश्यक कार्य होने पर ही घर व गांव से बाहर जाने के निर्देश है। वही संत तेरेसा की प्राचार्य एवं संचालकों ने सरकारी गाईडलाइन का उल्लंघन कर खवासा में बड़े बुक्स सेलर होने के बावजूद भी खवासा से 16 किलोमीटर दूर पेटलावद की रूपांकन स्टेशनरी से बुक खरीदने के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है। जो सीधे रुप से सिद्ध करता है कि प्राचार्य एवं संचालकों ने स्थानीय लेवल से कमीशन नहीं मिलने के चलते पेटलावद बुक्स सेलर द्वारा कमीशन के लालच देने पर कमीशन के चलते पेटलावद से खरीदने के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है। पालकों ने बताया कि, स्कूल में कौन सी बुक्स लग रही है लिस्ट मांगने पर भी प्राचार्य सिस्टर टेसिया लिस्ट नहीं दे रही है। सीधे मौखिक व स्कूल के बने व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना दी जा रही है कि, संत तेरेसा स्कूल की पुस्तके रूपांकन प्रिंटर्स मेन रोड शंकर मंदिर के सामने पेटलावद संचालक निलेश पालीवाल से ही अनिवार्य रूप से खरीदना है, जिसका हम विरोध करते हैं। पालकों ने कहा, अगर स्कूल से हमें स्कूल में लगने वाली बुक्स की लिस्ट नहीं देते हैं, तो हमारा स्कूल के प्रति विरोध रहेगा। पालकों का कहना है कि, खवासा में लिस्ट अनुसार बुक्स मिल सकती है तो हम पेटलावद जाकर किताबे क्यों खरीदेंगे।

इस संबंध में संस्था की प्राचार्य सिस्टर टेसिया से चर्चा की तो, एक चपरासी की तरह हास्यप्रद जानकारी देते हुए बताया, स्कूल में लगने वाली कौन सी बुक्स है संस्था में हमें किसी को पता नहीं है, सीधे पेटलावद से रूपांकन स्टेशनरी से बात होकर उसी दुकान से किताबों का खरीदना तय हुआ है। बुक्स का चयन किसने किया और रूपांकन स्टेशनरी पेटलावद से खवासा स्कूल संत तेरेसा स्कूल की बुक्स खरीदना होगा, यह किसने तय किया...? के जवाब में प्रिंसिपल सिस्टर टेसिया कहती है, यह भी मुझे नहीं मालूम।

संत तेरेसा स्कूल ग्रुप पर खवासा से 16 कि.मी. दुर पेटलावद की रूपांकन स्टेशनरी के निलेश पालिवाल से किताबे खरिदने हेतु मेसेज सेंड कर पालकों को किया जा रहा प्रतिबंधित।

इस संबंध में पालकों का कहना है कि, प्राचार्य सिस्टर टेसिया को कुछ नहीं मालूम तो यहां की प्राचार्य किसने नियुक्त किया, जो चपरासी से भी गिरे हुए जवाब दे रही है।

### अघोषित बिजली कटौती बन्द करने की मांग

**माही की गूंज, पेटलावद।** पेटलावद विधायक वालसिंह मैड़ा के नेतृत्व में बुधवार को भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज़ सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहा कांग्रेस ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती पर सरकार को साधते हुए बिजली कटौती बन्द करने के लिए ज्ञापन सौपा।

पेटलावद ब्लाक के कार्यवाहक अध्यक्ष जीवन सिंह ठाकुर ने बताया कि, भाजपा सरकार ने बिना बताए ओर बिना कारण क्षेत्र में बिजली कटौती शुरू कर दी। जिससे किसान, छात्र वर्ग, महिलाएं सहित व्यापारियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। आमजन की इसी परेशानी को देखते हुए सरकार द्वारा की जा रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में ज्ञापन सौंपकर कटौती बन्द करने की मांग की है। इस दौरान विधायक वालसिंह मैडा, पेटलावद ब्लाक अध्यक्ष सुरेश मुथा, सारंगी ब्लाक अध्यक्ष अग्निनारायन सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हनुमंत सिंह डाबड़ी, विधायक प्रतिनिधि मन्ना हामड, आईटी सेल विक्रम चावड़ा, युवा नेता शैलेन्द्र सिंह गंगाखेड़ी, ब्लॉक महामंत्री कयूम शेख सहित कई कार्यकर्ता और महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता उपस्थित रही।

### बढ़ते अपराधों को लेकर युवा कांग्रेस ने किया पुतला दहन

**माही की गूंज, बरझर।**

युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया के आह्वान एवं युथ कांग्रेस जिला प्रभारी पुनीतसिंह पारिया के निर्देशन में प्रदेश मे बढ़ते अपराधों की घटनाओ के विरोध स्वरूप बुधवार को पुतला दहन किया गया। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष तरुण मंडलोई एवं युवा नेता पुष्पराज पटेल के नेतृत्व में अलीराजपुर शहर में प्रदेश में सत्तारूढ रावण रूपी भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। उक्त पुतला दहन के दौरान पुलिस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बिच खिंच-तान और झूमा-झटकी भी हुई। इसी बिच युवाओं ने पुतले को आग के हवाले कर दिया, अर्धजले पुतले को पुलिस ने अपने कब्जे में'लेकर बुझाया।

पुतला दहन के बाद युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष तरुण मंडलोई ने कहा, मध्यप्रदेश सरकार में आदिवासीयो पर जिस तरह से अमानवीय घटनाए घटित हो रही है, उन्हे सुनकर दिल दहल जाता है। अपराधीयों के सामने प्रदेश सरकार लाचार है। आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों वर्गो पर लगातार अपराध बढते जा रहे है। इसके पहले इंदौर, देवास, सतना, रीवा, आदि जगह पर घटना हो चुकी है। विगत दिनो सिंगरोली के आदिवासी कन्हैयालाल भील को पहले तो बुरी तरह पीटा गया। बाद में उसे एक वाहन से बांधकर घसीटा गया व बड़ी ही निर्दयता से उस पर अमानवीय यातनाएं दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना मानवता और प्रदेश के मस्तक पर कलंक है, इस तरह के कृत्य की युवा कांग्रेस कड़ी निन्दा करता है।

पुतला दहन के दौरान प्रदेश कांग्रेस सचिव जाहिर मुगल, यूवा नेता सोनू वर्मा, प्रदीप रावत, धानसिंह चोहान, इरफान मंसूरी, मनीष चौहान, इरशाद चंदेरी, पिंटू सेन, सुरेंद्र चौहान, अंगरसिंह, प्रदीप सोनी, सलमान मकरानी, प्रकाश बघेल, जुवान डुडवे, वसीम लाला, विक्रम चौहान आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

### आशा पर्यवेक्षक तथा सेहत सखी को दिया गया प्रशिक्षण

**माही की गूंज, झाबुआ।**

मातृ मृत्यु तथा शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मध्यप्रदेश वोलंटरी हेल्थ एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और संस्था एकजुट के तकनिकी सहयोग से सहभागी सीख तथा क्रियान्वयन (पीएलए) परीयोजना का संचालन जिला मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपीएस ठाकुर और डिस्ट्रीक्ट कम्युनिटी मोबीलायजर मुकेश यादव के मार्गदर्शन में झाबुआ जिले के दो विकासखंड थांदला तथा रामा में क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत आशा पर्यवेक्षक तथा सेहत सखी को एकजुट संस्था द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रतिभागियों को मातृ मृत्यु तथा शिशु मृत्यु कम करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी दी गई।

### डिजिटल माध्यम से योग चिकित्सा करने वाले कर्मियों का किया सम्मान

**माही की गूंज, बड़वानी।** कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान डिजिटल योग चिकित्सा देने वाले आयुष विभाग के पदाधिकारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है।

जिला आयुष अधिकारी डॉ. एचएस तोमर ने बताया कि, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान डॉ. एवं योग वालेंटियर्स डॉ. छगन जामोद, डॉ. मोतीलाल अवास्या, डॉ. अछाले, डॉ. दुर्गा पंवार, डॉ. बाली चैहान, डॉ. नरेन्द्र मण्डलोई, डॉ. हेमंत करोले, डॉ. सैनानी, डॉ. टीएस मेहता, डॉ. मनोज चैहान, वालेटियर भगवान चैहान, महेश राठौर, श्याम जोशी के द्वारा आपातकालीन सेवा के तहत घर-घर जाकर आयुर्वेद एवं होम्योपेथी दवाईयों का वितरण, कोविड सेम्पलिंग, योग चिकित्सा में दिए गए सहयोग के लिये प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है।

### जुड़वा बहनों को मिली डाक्टरेट की उपाधि

**माही की गूंज, बड़वानी।**

जिले की दो जुड़वा बहनों को बर्कतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा वनस्पति शास्त्र में किए गए शोध कार्य हेतु पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। बड़वानी की रहवासी पायल जोशी एवं नुपूर जोशी की सम्पूर्ण पढ़ाई बड़वानी में ही पूर्ण हुई है। जुड़वा बहनों की इस उपलब्धि पर उनके परिजनों एवं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के प्राध्यापको ने खुशी व्यक्त की है।

पायल जोशी एवं नुपूर जोशी ने अपना पीएचडी शोध कार्य शासकीय महाविद्यालय होशंगाबाद के प्राध्यापक डॉ. केडब्ल्यू शाह के निर्देशन में पूर्ण किया है। पायल जोशी के इस शोध से मूंग की फसल वृद्धि में विभिन्न बैक्टेरियल बॉयोइनाकुलेंट के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि तथा कुमारी नुपूर जोशी के शोध से कददू एवं किकोड़ा (कटला) के विभिन्न भागो से प्राप्त रसायनो से एंटीमाइक्रोबियल एवं कैंसर रोग के उपचार को नई दिशा प्राप्त होगी। वर्तमान में नुपूर जोशी शासकीय महाविद्यालय कायथा उज्जैन में तथा पायल जोशी एसबीएन कालेज बड़वानी में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत है।

### उपचुनाव की सुगबुगाहट के साथ लोगो को लुभाने हेतु राजनीतिक दौरे शुरू

**माही की गूंज, बरझर।**

आगामी जोबट विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए आजाद नगर भाबरा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों का आना-जाना प्रारम्भ हो गया है। जिसके चलते जिला प्रभारी मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव, बड़वानी-खरगोन सांसद गजेन्द्र सिंह पटेल, ज़िला पंचायत अध्यक्ष धार मालती मोहन पटेल ने सेजावाडा, बडा खुटाजा व झोतराडा में जनसभा को संबोधित किया।

सभा को संबोधित करते हुए राजवर्धन दत्तीगाव ने कहा कि, प्रदेश सरकार ने अनेकों जनकल्याण योजनाएं लागु कर रखी है। जिसमे महिलाओं की डीलेवरी से लेकर बच्चों की पढ़ाई व शादी तक करवाने की योजना शामिल है। इन योजनाओं का लाभ आगे आकर आप लोगों को लेना चाहिए।

बड़वानी-खरगोन सांसद गजेन्द्र सिंह पटेल ने कहा कि, जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से प्रदेश में विकास होता दिख रहा है। बिजली, सड़क, शिक्षा के क्षेत्र में शिवराज सरकार ने हर गांव व शहरों में काम किया है।

इस अवसर पर धार जिला पंचायत अध्यक्ष मालती मोहन पटेल, पुर्व थांदला विधायक कलसिंह भाभर, भाजपा के वरिष्ठ नेता सोमसिंह सोलंकी, राकेश अग्रवाल, अजय जायसवाल ने भी सम्बोधित किया।

#### ग्रामीण महिलाओं ने बांधी राखी

बडा खुटाजा में बड़ी संख्या में प्रभारी मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव व सांसद गजेन्द्र सिंह पटेल के स्वागत में आई महिलाओं ने तिलक लगाकर राखी बांधी। साथ ही सभा में आई सभी महिलाओं को साड़ीयां देकर सम्मान किया और आशिर्वाद लिया।

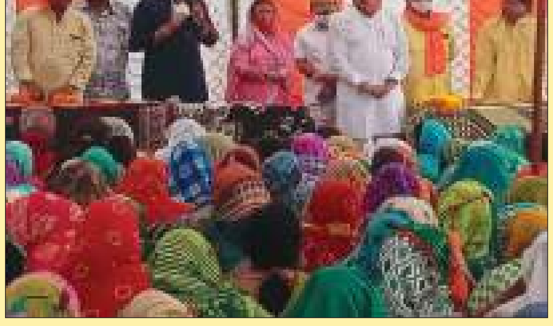

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष वकील सिंह ठकराला, पुर्व थांदला विधायक कलसिंह भाभर, पुर्व विधायक माधवसिंह डावर, सोमसिंह सोलंकी, पुर्व जिलाध्यक्ष राकेश अग्रवाल, अजय जायसवाल, रमणलाल चौहान, जितेन्द्र पंचाल आदि मोजुद थे।

### लुट को अंजाम देने आए बदमाश हवाई फायर कर हुए रफुचक्कर

**माही की गूंज, पारा।**

ग्राम में अज्ञात बदमाशो के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों को पुलिस का जरा भी भय नहीं रह गया है। ग्राम में लगातार होती चोरी के सिलसिले में फिर अज्ञात बदमाशों ने चोरी का प्रयास किया, मगर चोरी करने में नाकाम रहे। शुक्रवार रात के दर्मियान बोरी रोड चौराहों पर निर्माणाधिन दुकान में काम करने वाले मजदूर सोएं हुए थे। देर रात में बदमाश उसी दुकान के पास छिपे हुए थे। जब मजदुर व मकान मालिक को बदमाशो की भनक लगी तो मालिक ने पड़ोसियों को फोन लगाकर सूचना दी, जिससे सभी मोहल्लेवासी उठ गए। वहीं लोगो को देखकर बदमाश भाग निकले। बदमाशो से बचने के लिए लोगों ने हवाई फायर भी किया। उक्त घटना की जानकारी पारा पुलिस को देने के कुछ समय पश्चात पुलिस घटनास्थल पर पहुंची व बदमाशो का पीछा भी किया, परन्तु बहुत देर हो गई थी बदमाश भागने में सफल हो गए।

बता दे कि, उक्त स्थान के सामने एक मेडिकल स्टोर पर पिछले दिनों बदमाशों ने ताले तोड़कर हजारों की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। सूत्र बताते है कि, बदमाश रोजाना ग्राम में प्रवेश कर रहे है। बदमाशो ने स्थानीय पुलिस की नाक मे दम कर रखा है। इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि, पुलिस की निष्क्रियता से चोर सक्रिय होने लगे है।

# रोजगार सहायक के भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामवासियों ने की कलेक्टर से शिकयत

## आलीराजपुर और आम्बुआ में अलग-अलग संगठनों ने अलग-अलग मुद्दों पर दिए ज्ञापन

**माही की गूंज, अलीराजपुर।**

अलीराजपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अजन्दा के ग्रामवासियो ने रोजगार सहायक माधु सोलंकी द्वारा किए जा रहे पंचायत में लगातार भ्रष्टाचार व घोटालो की शिकायत कलेक्टर से की। ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि, रोजगार सहायक माधु सोलंकी द्वारा वर्ष 2012 से शासन की विभिन्न योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मेढ़ बंधन योजना आदि में मनमानी एव भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उपरोक्त शासकीय योजनाओं में स्वीकृत पूरी राशि आज तक हितग्राहियों के खाते में नही डाली गई है।

शिकायत के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि, भ्रष्ट रोजगार सहायक माधु सोलंकी विभिन्न शासकीय योजनाओं में स्वीकृत राशि संबंधित हितग्राहियों के बैंक खातो में न ड़ालकर अपने सगे संबंधी के बैंक खातो में राशि डलवाकर, बैंक से निकलवाकर अपनी जेब भरने का कार्य कर रहा है। यदि कोई इस संबंध में आपत्ति लेता है तो उसे जान से मारने की धमकी तक देने में पिछे नही हटता है।

ग्रामीणों ने मांग की कि, ग्राम पंचायत अजन्दा के रोजगार सहायक द्वारा किए गए भ्रष्टाचार व घोटालो कि विस्तृत जांच कर कानुनी कार्रवाई के साथ उसकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए, अन्यथा एक हफ्ते बाद पूरे ग्रामवासी कलेक्टर कार्यालय पर आकर हड़ताल व धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन-प्रशासन की होगी।

## बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने वालों पर हो कार्रवाई

**माही की गूंज, आम्बुआ।**

मध्यप्रदेश बेरोजगार संगठन पर विगत दिनों राजधानी भोपाल में रोजगार की मांग कर रहे युवक-युवतियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग का ज्ञापन आम्बुआ थाने पर दिया गया।

विगत 4 वर्षो से प्रदेश में किसी भी तरह के रोजगार हेतु रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कोई विज्ञप्ति शासन द्वारा नहीं निकाले जाने से बेरोजगार युवा विगत महीनों से रोजगार की मांग हेतु आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेरोजगार युवक-युवतियों ने आंदोलन करते हुए मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वालों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया गया जिसमें कई घायल भी हुए। वही आंदोलन करने वाले लगभग 154 लोगो के खिलाफविभिन्न धाराओं में प्रकरण कायम किया गया। बेरोजगार संगठन द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन आम्बुआ थाना प्रभारी के माध्यम से भेजे जाने हेतु मांग पत्र सौंपा गया जिसमें रोजगार देने के साथ-साथ जिन युवाओं पर प्रकरण दर्ज किया गया है, वह प्रकरण वापस लेने की मांग भी ज्ञापन में की गई है तथा बल प्रयोग करने वालो की जांच की जाकर कार्रवाई की मांग भी की गई।

## विश्व आदिवासी दिवस का विरोध करने वालों पर कार्रवाई करने हेतु सौंपा ज्ञापन

**माही की गूंज, आम्बुआ।**

विगत दिनों 9 अगस्त को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस के समय समाचार-पत्र और न्यूज़ चैनलों तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाकर विरोध जताने वाले प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्रियों आदि पर कानूनी कार्रवाई हेतु महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम सर्व आदिवासी समाज की ओर से एक ज्ञापन आम्बुआ पुलिस थाने में दिया गया।

सर्व आदिवासी समाज की भावनाओं को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर समाचार पत्रो, सोशल मीडिया एवं न्यूज़ पर खरगोन-बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, पंधाना (खंडवा) विधायक रामदांगोरे, बागली (देवास) विधायक पहाड़सिंह कन्नौज, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा मध्यप्रदेश अध्यक्ष कलसिंह भाबर तथा मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव लक्ष्मण सिंह राज मरकाम द्वारा भ्रामक तथ्यहीन व मिथ्या जानकारी देकर आदिवासी समाज को गुमराह कर अपमानित करने का प्रयास किया, जिससे आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। महत्वपूर्ण पदों पर बैठे ऐसे जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियो, अधिकारियों के खिलाफतत्काल सख्त कार्रवाई एवं उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग का ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली तथा राज्यपाल मध्यप्रदेश शासन के नाम आम्बुआ पुलिस थाने पर पदस्थ थाना प्रभारी योगेंद्र सजोतिया को ज्ञापन सौंपा।

# फूटा घर, फूटी किस्मत दर-दर भटक रहे गरीब

## नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

**माही की गूंज अलीराजपुर।**

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर गरीब को पक्का घर देने का वादा ''चतरा में सफेद हाथी'' साबित हो रहा है। वर्षो से अत्यंत गरीब परिवार के लोग अपने घर के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक पक्का घर नहीं मिल पाया है।

मामला अलीराजपुर जिले के नानपुर ग्राम पंचायत के कोटवाल फलिए का, जहां नानपुर के मुलेसिंह मौर्य युवा नेता के नेतृत्व में कोटवाल फलिए के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुचे जहां नायाब तहसीलदार को ज्ञापन दिया, ज्ञापन में बताया गया कि, ग्राम कोटवाल फलिए में नल कनेक्सन एवं प्रधानमन्त्री आवास हमारे सभी वर्गों के लोगो के आवास आ चुके हैं। हम एससी वर्ग के लोग छुटे हुए हैं। हम लोग कई सालो से पिछडे हुए हैं। कोई भी समस्या का हल नहीं हैं ना आवास हैं, न नल कनेक्सन हैं, बिजली कि स्थिति बहुत कमजोर है वही सभी ग्रामीण मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। हर किसी को आवास कि अत्यन्त आवश्यकता हैं, जिस समय से आवास प्रक्रिया शुरू हुई हैं, तब से लगाकर आज तक कई बार आवेदन दे चुके हैं। लेकिन आज तक किसी भी समस्या का हल नहीं हुआ हैं।

नानपुर ग्राम से सरपंच एवं मन्त्री को भी कई बार मिले लेकिन फिर भी कोई निराकरण नहीं हुआ एससी वर्गो के लोगो को हर सुविधा का लाभ मिले बारिश के मौसम में हम लोगो को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सडक, आवास, बिजली एवं पानी हमारी गरीबी एवं आर्थिक स्थिति को समझते हुए हमारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए ज्ञापन दिया।

ज्ञापन देने के दौरान पिंकू गोयल, सुरेश गोयल, राकेश किराड़, मुकेश किराड़, अनिल गोयल, दिनेश किराड़, अनिल चौहान, वेस्ता सोलंकी, सर्ला गोयल, प्रताप चौहान, धर्मेंद्र गोयल, राजू सुनील, दिलीप, कालू, गुड्डू, सिमरिया, रेमसिंह उपस्थीत रहे।

## वर्षा जनित बीमारियों ने पांव पसारे, दवा नहीं छिड़कने से मच्छरों की भरमार

**माही की गूंज, आम्बुआ।** क्षेत्र में बारिश की अनियमित्ता बनी हुई है, कम वर्षा के बावजूद जहां-तहां गड्ढों में भरे पानी में मच्छरों की भरमार हो रही है, गटरों पर पसरे अतिक्रमण के कारण सही तरीके से सफाई नहीं होने से भी मच्छर पनप रहे है, दवा का छिड़काव नहीं होने से मच्छरो की भरमार हो गई है।

क्षेत्र में इन दिनों मरीजों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि वर्षा जनित बीमारियों के कारण बताई जा रही है, क्षेत्र में अभी कोरोना के मरीज तो नहीं मिल रहे हैं मगर सर्दी, खासी, बुखार के मरीजो की चिकित्सालयों में भीड़ बढ़ रही है। बीमारों में बच्चों की भी संख्या दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस की बीमार के डर के कारण लोग अस्पतालो की बजाए निजी तथा झोलाछाप चिकित्सकों के पास इलाज करा रहे हैं, कस्बे में गटरों के ऊपर अतिक्रमण होने से सफाई कर्मी सफाई नहीं कर पा रहे हैं जिस कारण भी मच्छर पनप रहे हैं, भविष्य में मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया के साथ-साथ कोरोना का वार न हो जाए इसकी आशंका बनी हुई है।

## सेवानिवृत्त पर समारोह आयोजित कर दी विदाई

**माही की गूंज, झाबुआ।** मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में मत्स्य विभाग के सहायक संचालक यूसी भाटी के सेवानिवृत्त अवसर पर समारोह पूर्वक विदाई दी गई। इस अवसर पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको बधाई देते हैं। अब शेष समय आप अपने परिवार को दें और धार्मिक यात्रा कर इसका आनंद लें। कलेक्टर मिश्रा ने भाटी का पुष्पहार से अभिनंदन और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

# कोरोना नियमों के पालन के साथ मनाई जन्माष्टमी दही हांडी का कार्यक्रम नहीं होने से हुए निराश

**माही की गूंज, आम्बुआ।**

भगवान श्री कृष्ण का जन्मउत्सव जन्माष्टमी इस बार भी कोरोना की भेंट चढ़ गया मंदिरों में पूजा-अर्चना, आरती आदि की गई मगर सार्वजनिक दहीहंडी का कार्यक्रम नहीं होने के कारण ग्रामीण निराश होकर लौटे।

देवकीनंदन माता यशोदा के लाडले भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है, मगर इस बार कोरोना नियमों के कारण प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने से सार्वजनिक दही हांडी का आयोजन नहीं हो सका। दही हांडी फोड़ने वाले गोविंदाओं की टोलियां के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों से बाजार में कार्यक्रम देखने आने वाले ग्रामीण भी निराश होकर लौट गए, इस आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण आते हैं तथा दही हांडी उत्सव एक मेले जैसा कार्यक्रम हो जाता था मगर इस बार निराशा का माहौल रहा।

कई परिवारों ने व्यक्तिगत रूप से नंदलाला की झांकियां सजाकर जन्मोत्सव मनाया मंदिर में भी भजन-पूजन के बाद रात्रि 12 बजे ÷भए प्रगट कृपाला÷ स्तुति के साथ आरती की गई नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जैसे अनेक मनमोहक नारों के से वातावरण कृष्णमय हो गया, आम्बुआ में पुजारी शंकर लाल पारीख ने पूजा-अर्चना, आरती के पश्चात प्रसादी वितरण की।

# बिजली ट्रांसफॉर्मर के अर्थिंग तार से करंट लगने के कारण दो बैल की मौत, बाल-बाल बचा कृषक

**माही की गूंज, आम्बुआ।**

ग्राम पंचायत क्षेत्र के गाता फलिया में खेत पर बेल लेकर जाते हुए बिजली ट्रांसफॉर्मर के पास से गुजरते समय अर्थिंग तार से करंट लगने के कारण दो बैलों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। थाना आम्बुआ में घटना की सूचना दी गई, बिजली विभाग के कर्मचारी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर विवेचना की।

जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र के गाता फलिया निवासी रणसिंह पिता दलसिंह भिलाला (35) ने पुलिस थाना आम्बुआ में सूचना देते हुए बताया कि, सोमवार सुबह वह अपने दो बैलों को लेकर खेत पर जा रहा था। गाता फलिया निवासी करण सिंह के घर के पीछे लगी डीपी (बिजली ट्रांसफार्मर) के पास से गुजरते हुए डीपी के अर्थिंग तार से बैलों को करंट लगा, जिस कारण दोनों बैलों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। करंट लगते ही रणसिंह बेलों से दूर हट गया, वरना वह भी चपेट में आ जाता। घटना की सूचना आम्बुआ थाने के साथ-साथ बिजली विभाग को भी दी गई। बिजली विभाग के कर्मचारी ने घटनास्थल पर जाकर बिजली बंद की थाना आम्बुआ पर प्रकरण कायम कर एएसआई धर्मेंद्र सोमवंशी को जांच हेतु अधिकृत किया गया है। घटना में एक साथ दो बैलों की मौत से कृषक परिवार में मातम पसरा है, आगे भविष्य में कृषि कार्य कैसे करेगा यह सवाल उसके सामने खड़ा है।

# जल भराव से परेशान होकर सीएम हेल्पलाइन पर की थी शिकायत

## बिना किसी जानकारी के कर दिया निराकरण

**माही की गूंज, झकनावद।**

नगर के मुख्य मार्ग जो कि धार जिले को झाबुआ जिले से जोड़ता है काफी खस्ता हालत में जा चुका है, जगह-जगह सड़क की जगह अब गड्ढो ने ले ली है, सबसे ज्यादा खराब हालत ग्राम झकनावदा में है जहा सड़क के एक हिस्से ने तालाब का रूप ले लिया है। हालांकि यहां 12 महीने पानी और कीचड़ रहता है, लेकिन बारिश में स्थिती और खराब हो जाती है, जिससे पैदल यात्रियों को व वाहन चालकों को भारी दिक्कतो का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कई बार संबंधी लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों तक गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार मामले को किसी न किसी बहाने से दबा दिया जाता है। गत दिनों समस्या से ग्रस्त रमेश सोलंकी ने सीएम हेल्पलाइन पर समस्या के निराकरण करने के लिए गुहार लगाई जहा से उन्हें शिकायत क्रमांक 14671057 देकर जल्द ही निराकरण का आश्वासन दिया गया।

### बिना किसी जानकारी के कर दिया निराकरण, अतिक्रमण और दोनों और भराव होने का दिया हवाला

शिकायतकर्ता को उम्मीद थी कि, सीएम हेल्पलाइन से गुहार लगाने के बाद शायद इस समस्या से निजात मिल जाए, लेकिन विभाग और ठेकेदार की और सीएम हेल्पलाइन पर ठीकरा ग्राम पंचायत और अतिक्रमण पर फोड़ कर जवाब दे दिया। वही हेल्पलाइन की और से बिना शिकायतकर्ता का मत जाने शिकायत का निराकरण कर दिया। निराकरण में बताया, रोड के दोनों और अधिक भराव और अतिक्रमण की वजह से सड़क के बीच गड्ढा हो गया है, जिसका निराकरण ग्राम पंचायत द्वारा पानी की निकासी हेतु नाली निर्माण होने के बाद ही सड़क को ठीक किया जा सकता है।

**सड़क हुई गायब, भराव तक करने को तैयार नही**

होना ये था कि, शिकायत का निराकरण सड़क में सुधार या भराव कर होना था जिससे कुछ समय के लिए लोगों को समस्या से निजात मिल जाती। मौके पर सड़क बताई जा रही है, जहां अतिक्रमण ओर पानी की निकासी नही होने से जल भराव होना बताया जा रहा है, जबकि मौके पर कोई सड़क नही है केवल बड़ा भारी गड्ढा बन चुका है। आई दिन उक्त स्थान पर दुपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे है, विभाग और ठेकेदार गड्ढे भरने की बजाए जिम्मेदार एक-दूसरे पर बिल फाड़े जा रहे है, जो प्रशासन की जन समस्याओं के प्रति लापरवाही को उजगार कर रहे है।

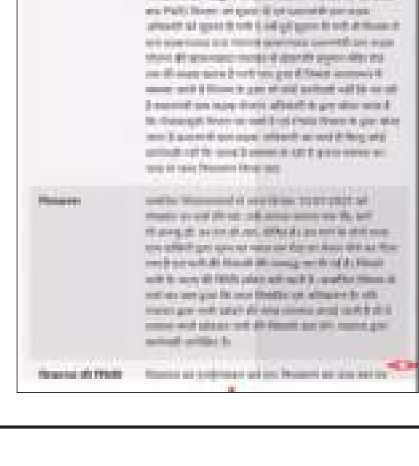

# धार्मिक स्थलों पर पांच गमले व पौधे देकर का दिया सन्देश, 1111 पौधे रोपें

**माही की गूंज, मेघनगर।**

मातृभूमि वृक्षारोपण के अंतिम चरण में धार्मिक एकता का संदेश मिला। जिसमें एक हजार एक सौ ग्यारह पोधरोपण करने का कार्य रोटरी क्लब अध्यक्ष निलेश भानपुरिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में 1008 महंत दयाराम दास महाराज, भारतीय मजदूर यूनियन संघ के मोहन प्रजापत, शिवगंगा प्रशिक्षण केंद्र के शंकर भाईसाहब, वरिष्ठ उद्योगपति विनोद बाफना, रोटेरियन भरत मिस्त्री, बहादुर सिंह चौहान, सचिव महेंद्र सोलकी व कवि चन्द्रलाल आदि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कॉल टू ऑडर मांगीलाल नायक ने किया।

रोटरी परंपरा अनुसार चतुर्वेद मंथ का वाचन रोटेरियन जयंत सिंघल ने किया। अपने स्वागत भाषण में रोटरी अध्यक्ष ने पोधरोपण का प्रथम, द्वितीय और अंतिम चरण तक की सारी रूपरेखा बताते हुए सभी पौधरोपण में सहयोग करने वाले मजदूर साथी का स्वागत व सम्मान किया, साथ ही आगामी प्रोजेक्ट के बारे में अवगत कराया।

कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार विमल जैन, प्रकाश भंडारी, सलीम शेरानी, दशरथ कट्ठा, अनूप भंडारी, सुनील डाबी, फारुख शेरानी, भूपेंद्र बरमंडलिया, मनीष गिरधानी, पंकज बडोला, जियाउलहक कादरी, रहीम हिन्दुस्तानी, निसार पठान, अली असगर, अभय राका आदि पत्रकारों का स्वागत रोटरी क्लब के सदस्य ने किया। आयोजन में पर्यावरण सहजने की दिशा में कवि शंकर सिंह चंद्रावत ने कविता प्रस्तुत की। आयोजन के दूसरे चरण में झाबुआ से पधारे चौक आर्टिस्टिक आशीष पांडे ने अखंड भारत व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चित्र चौक से बनाएं, जिसने सभी का आकर्षण जीत लिया। समारोह के तीसरे चरण में समाज रत्न स्व. सरस्वती बाई राका की प्रथम स्मरण पर रोटेरियन पंकज राका ने अपने उद्बोधन में श्रद्धांजलि दी व धार्मिक एकता का संदेश देते हुए नगर के धार्मिक स्थलों के परिजनों को 51 शोभा दार गमले वितरित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 1008 बाबा रामदास महाराज ने अपने प्रवचन में पोधरोपण में भगवान राम की मनमोहक कहानी सुनाकर प्रकृति के प्रेम का वर्णन किया। शिवगंगा केंद्र के प्रमुख शंकर व बच्चों ने अपने हाथों द्वारा बनाए गए बॉस के बम्बू से बनाए नाइट लैंप, मोबाइल स्टैंड आदि खूबसूरत सामानों को प्रदर्शित किया।

कार्यक्रम के अंतिम चरण में राका परिवार द्वारा माता जी की स्मृति में रोटरी क्लब के पंकज राका, निलेश भानपुरिया, गोविंद सिंह चौहान, मांगीलाल नायक, सुमित जैन, महेश प्रजापति, राजेश भंडारी, महेंद्र सिंह सोलकी आदि द्वारा ग्रामीण अंचल में भोजन के पैकेट जरूरतमंदों को बांटे गए। नगर के 10 से अधिक सर्व धर्म धार्मिक स्थलों पर पौधे और गमले वितरण का कार्य भी राका परिवार द्वारा किया गया। आभार क्लब के सचिव महेंद्र सिंह सोलंकी ने माना। आयोजन का संचालन शिवाली राका ने किया।

## अरोड़ा खत्री समाज ने मनाया दरियाव सप्तमी पर्व

**माही की गूंज, थांदला।** वरुण सप्तमी के पावन पर्व पर अरोडा खत्री समाज के समस्त समाजजन, सपरिवार भक्त मलुकदासजी खत्री द्वारा निर्मित समाज के आराध्यदेव श्री रामजी मंदिर पर एकत्रित होकर भगवान वरुण देव के चित्र एवं जलकलश की पूजा, आरती की गई। इस अवसर पर अरोडा खत्री समाज थांदला के अध्यक्ष ऐडवोकेट वीआर अरोडा, मध्यप्रदेश अरोड़ा खत्री समाज के महासचिव एवं अखिल भारतीय अरोडा खत्री महासभा के मीडिया प्रभारी कुन्दन अरोडा, रंगराय अरोडा, उपाध्यक्ष अशोक अरोडा, हरी विठ्ठल राय अरोडा, देवेंद्र अरोडा, मध्य प्रदेश अरोडा खत्री नवयुवक मंडल के सदस्य श्रीमंत अरोडा, संदीप अरोडा, धवल अरोडा, हार्दिक अरोडा, हिमांशु अरोडा, मयंक अरोडा, दक्ष अरोडा, एवं महिला मंडल से श्यामा अरोडा, तारा अरोडा, नीता अशोक अरोडा, मंजू अरोडा, प्रीति अरोडा, नीता श्रीमंत अरोडा, अंजलि अरोडा, दीप्ति अरोडा, प्रेक्षा अरोडा आदि समाजजन उपस्थित थे। आरती के बाद सभी ने एक दिन पूर्व बनाए गए ठंडे भोजन की प्रसादी को ग्रहण किया।

# महिला बाल विकास में एक और बड़े भ्रष्टाचार की खुल सकती है पोल

## सूचना अधिकार की जानकारी देने के नाम पर फर्जी बिलों की सेटिंग का मामला आया सामने, साड़ी सप्लाई मामले में जांच के घेरे में विभाग

**माही की गूंज, झाबुआ। संजय भटेवरा**

महिला बाल विकास परियोजना पेटलावद का कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। शासन की और से दी जाने वाली योजना सहित भर्ती और आंगनवाड़ी में होने वाले व्यय में भ्रष्टाचार के बड़े मामले उजागर हो रहे है, वर्तमान में पेटलावद महिला परियोजना का कार्यालय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और साहियका के लिए साड़ी के लिए राशि का भुगतान किया गया था, जिसका सेटिंगबाज सप्लायरों की सेटिंग ओर सुपरवाइजर की मिलीभगत से घटिया साड़ी की सप्लाई का मामला सामने आ चुका है, जिसमे जिला कलेक्टर के निर्देश पर जांच शुरु हो चुकी है। लेकिन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई एक जानकारी से विभाग के एक ओर बढ़े भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है।

### वर्ष 2015-16 में तर्थत समिति के तहत सामान खरीदी में हुआ बड़ा घपला

शासन द्वारा आंगनवाड़ियों के माध्यम से छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत आंगनवाडीयो की सुविधा के सामान खरीदी के लिए 30 से 50 हजार रुपए का भुगतान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के खाते में राशि का भुगतान किया गया था, जिसका खर्च तर्थत समिति के माध्यम से किया जाना था और सामान खरीदी के बिल लगाना था। लेकिन सूचना अधिकार में मांगी गई जानकारी के बाद पता चल रहा है कि, पेटलावद परियोजना के कार्यालय में अधिकांश आंगनवाड़ियों का कोई हिसाब किताब नहीं है, जिस कारण अब तक जानकारी नही दी जा सकी है, क्योंकि चाही गई जानकारी बिल बाउच्चर, बैठक रजिस्टर, पासबुक की एंट्री आदि की प्रमाणित प्रति मांगी गई है जो कि विभाग के पास नही है।

### पुराने फर्जी बिल किए जा रहे है तैयार, पेटलावद की एक फर्म 10 प्रतिशत कमीशन पर बिल देने का कर रही दावा

महिला बाल विकास द्वारा जानकारी को लेकर अब पुराने फर्जी बिल बना कर देने की तैयारी शुरू कर दी है या यूं कहें कि परियोजना अधिकारी द्वारा जिन-जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उस समय बिल नही दिए थे उनको पुराने 2015-16 की तारीख के बिल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए है, एक आंगनवाडी कार्यकर्ता ने नाम न छापने की तर्ज पर बताया कि, परियोजना अधिकारी द्वारा एक निश्चित स्टेशनरी की दुकान पर से बिल लेने की सेटिंग जमा ली है और वही से पास बुक इंट्री के अनुसार बिल पर कमीशन देकर बिल लेना है। मामले की जानकारी एक और आरटीआई कार्यकर्ता को मिली तो मामले की जानकारी विभाग से मांगने के साथ-साथ नगर की प्रसिद्ध स्टेशनरी फर्म पर फोन लगा कर तर्थत समिति के तहत हुए खर्च के बिल लेने की बात की जिस पर दुकान दार ने पास बुक साथ लाने पर बिल देने की हामी भर दी जिसके लिए कमीशन का भुगतान करने का कहा गया। दुकानदार ने कमीशन के आंकड़े का खुलासा पासबुक इंट्री देख कर करने और मिल कर तय करने को कहा गया, मिली जानकारी अनुसार उक्त फर्म पर 10 प्रतिशत कमीशन पर पुरानी तारीख के बिल उपलब्ध करवाए जा रहे है।

### रिकॉर्ड जप्त कर जांच जरूरी, आंगनवाड़ियों से गायब है खरीदा हुआ सामान

महिला बाल विकास परियोजना में ऐसा किसी एक योजना में नही बल्कि शासन की ज्यादातर योजना में ऐसी ही लापरवाही की गई है। शासन की ओर से दी गई राशि को बिना किसी खरीदी के खाते से निकाल कर कोई बिल या रिकॉर्ड कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है, यदि प्रत्येक आंगनवाड़ी के खर्च, बिल और आंगनवाड़ी में उपलब्ध सामग्री का मिलान किया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तर्थत समिति द्वारा की गई खरीदी के बिलो के भुगतान की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए लगी आरटीआई की जानकारी आने के बाद भी फर्जी बिलो के इस खेल का खुलासा हो सकेगा। लेकिन एक बात तो साफ है तर्थत समिति के माध्यम से बड़े खेल को अंजाम दिया गया है, जिसके चलते फरवरी माह में मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए वर्तमान में बिलो की जुगाड़ की जा रही है।

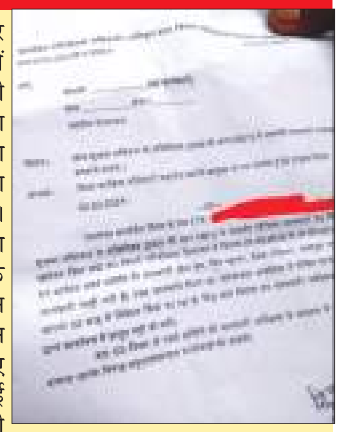

# लाखों की रिकवरी वसुली के लिए नोटिस पर नोटिस आखिर कब तक?

## प्रशासन का अंधा कानूनः वसुली नोटिस केवल निकल रहे खुद की वसूली के लिए, शासन को चुना लगाने वाले आज भी कर रहे भ्रष्टाचार

**माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत**

भ्रष्टाचार पुर बन चुका पेटलावद विकास खंड अब भ्रष्टो का सबसे सुरक्षित गढ़ बन चुका है, यहां किसी भी स्तर के भ्रष्टाचार को अंजाम देने और उसमे पकड़े जाने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नही होती है और कार्रवाई के नाम पर होती है अवैध वसुली जो अधिकारी करते है। कार्यवाही के नाम पर और शासन की राशि को चुना लगाने वाले बेफिक्र होकर आगे फिर लाइसेंस लेकर लूट पाट की तैयारी में लग जाते है। पेटलावद विकास खण्ड में ही नही लगभग 50 से ज्यादा या यूं कहें लगभग पंचायते ऐसी है जहां सिर्फपिछले 7 वर्षो के रिकॉर्ड की जाँच की जाए तो करोड़ो रूपए के काम जो कागज पर तो है, लेकिन जमीन स्तर पर या तो गायब है या अधूरे पड़े है या उनका निर्माण इतने घटिया स्तर से किया गया है कि उसका उपयोग आज तक आम जन नही कर पा रहे। हालांकि कही शिकायत तो कही जिम्मेदारों की मिलीभगत से जांच में मामले दबा दिए, तो कुछ एक मामलो में खुला भ्रष्टाचार और लाखों की रिकवरी करने के आदेश हो गए जो आज भी वसुली के नाम पर अधिकारियों की वसूली का जरिया मात्र बन कर रह गए।

### खोरिया, असलिया और तारखेड़ी पंचायत से होनी थी लाखों की रिकवरी

बात करे झाबुआ जिले की तो ऐसी कई पंचायते है जहा अधिकारी जांच में खुले भ्रष्टाचार को अनदेखा कर दबा नही सके और वसुली के लिए आदेश जारी करने पड़े है। पेटलावद विकास खण्ड में भी ऐसी काई ग्राम पंचायत है जिनसे लाखो की वसूली होना है जिसमे हमारी जानकारी में खोरिया, असलिया और तारखेड़ी पंचायत है जहां तीनो पंचायत से मिला कर 50 लाख से अधिक की वसूली के आदेश प्रशासन द्वारा जारी किए जा चुके है। लेकिन वसुली के नाम पर लगातार कई नोटिस जारी होने के बाद एक भी पंचायत द्वारा न तो राशि जमा की न ही काम किए और राशि वसुली के नोटिस मात्र अधिकारीयो की वसूली मात्र का जरिया बन गए जिसके तहत हर बार मामला उठने या शिकायत आने पर दिखावे के लिए फिर से नोटिस जारी कर अंत में निश्चित समय मे राशि जमा नही करने पर अपराध दर्ज होने की धमकी दी जाती है, जिसके चलते संबधित ग्राम पंचायत के सरपंच-सचिव जिले में बैठे अधिकारीयो के लिए भारी भरकम लिफाफे की भेंट पूजा कर फिर से मामले को कुछ समय के लिए दबा देते है। शासन की राशि से कोई वसूली हो न हो लेकिन वसुली के नाम पर अधिकारी अपनी वसुली कर नोटिस को कचरे के ढेर में डाल कर भूल जाते है।

### बिना कार्य किए फर्जी बिलों के माध्यम से निकाल ली राशि

पेटलावद विकास खण्ड की खोरिया, असलिया, तारखेड़ी सहित विकास खण्ड की कई पंचायतो द्वारा पंच परमेश्वर योजना के तहत वर्ष 2016 से 2019 तक में सड़क, नाली निर्माण सहित कई निर्माण कार्य करने के नाम पर बिना धरातल पर काम किए कागज पर काम बताकर फर्जी बिलो के माध्यम से राशि हड़प ली जिसकी जांच के बाद कई पंचायतो ने बकाया निर्माण करने के नाम पर कार्रवाई को रोक लिया तो खोरिया, तारखेड़ी, असलिया जैसी पंचायतो से शासन ने रिकवरी शुरू कर दी जो कि लगभग दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अधूरी है तो कई पंचायतो के बाकी पड़े निर्माण के दावे आज भी अधूरे है या फिर निम्न स्तर पर निर्माण कर मामले को रफा-दफा कर दिया तो कई पंचायतो ने नए कामो की सामग्री पुराने बाकी कार्यो पर डलवा कर कार्य शुरू होने का झांसा देकर अधिकारीयो को गुमराह कर दिया।

### चोरी पकड़ी जाए तो अपराध दर्ज नहीं वसुली होगी ये कानून की कैसी परिभाषा...?

विगत दिनों 15 अगस्त को एसडीएम गेमावत के साथ हुई पत्रकारो की बैठक में पंचायतो में मचे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस हुई थी, जिसके बाद एसडीएम गेमावत ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई बड़ी पहल देखने को नही मिली है। वही जिले में बैठे अधिकारीयो ने अपराध और कानून की परिभाषा ही बदल कर रख दी, अनुमन कोई चोर पकड़ा जाता है तो पुलिस उस पर अपराध दर्ज कर उसे जेल भेजती है, लेकिन शासन की राशि गबन करने वालो पर अधिकारी अपराध दर्ज करने की बाज़ए राशि वसूले ओर बाकी पड़े कार्य करवाने के लिए दबाव डालती है और लगातार नोटिस देने के बाद भी जब राशि जमा नही होती तब भी अपराध दर्ज नही करवाया जाता जो सीधे-सीधे कानून का मज़ाक उड़ाने जैसा है, जबकि सामान्य चोरी के मुकाबले शासन की राशि के साथ गबन, हेरा-फेरी, धोखाधड़ी और अमानत में ख्यानत करने वालो पर और भी गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज होते है जो कि आज तक नही करवाए जा सके जिसके पीछे अधिकारीयो की भ्रष्ट मंशा साफ जाहिर होती है।

### ग्राम पंचायतों को मिल चुका है भ्रष्टाचार का खुला लाइसेंस

जिम्मेदार अधिकारी की भ्रष्ट पिपासा कहे या लापरवाही या खुद के अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को दबाने की प्रक्रिया, शासन में बैठे अधिकारीयो के इस रवयै के कारण ग्राम पंचायतों को भ्रष्टाचार का खुला लाइसेंस मिल गया है, जिसके तहत हर पंचायत में, हर योजना में खुला भ्रष्टाचार और हितग्राहियों से खुली वसुली का खेल चल रहा है, जिसकी आए दिन शिकायते हो रही है लेकिन कार्रवाई तो ठीक, जांच तक नही की जा रही और जनपद स्तर से ही मामला दबा दिया जा रहा है।

### बड़ी कार्रवाई की दरकार ताकि भ्रष्टों में बन सके भय का माहौल

शासन से लाखों रुपए का वेतन, कोई शासकीय सुविधा का लाभ ले रहे अधिकारी भ्रष्टाचार जीवी बन चुके और अपने कर्तव्य के प्रति थोड़े भी जिम्मेदार नही है, जबकि वर्तमान स्थिति में प्रशासन की और भ्रष्टाचारियो पर बड़ी कार्रवाई की दरकार है, जिससे विकास खण्ड की जड़ो में धुस चुके भ्रष्टाचार को कुछ हद तक लगाम लग सके साथ ही भ्रष्टाचारियो में भय का माहौल बने, जिस तरह से शासन की राशि मे फर्जीवाड़ा किया गया है उस पर सीधा अपराध दर्ज करवाकर भ्रष्टाचारियो और उनके सहयोगीयो को जेल भेजने की प्रक्रिया करनी चाहिए जिसकी उम्मीद वर्तमान अधिकारीयो से करना शायद धोखा होगा।

# शोरूम संचालक फैला रहा कचरा, स्वछता अभियान को लग रहा पलीता

**माही की गूंज, बामनिया।**

ग्राम के पेटलावद मार्ग पर स्थित दुपहिया वाहन के शोरूम और सर्विस सेंटर द्वारा निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को खुले में फेंका जा रहा है, जिससे ग्राम में प्रवेश करते ही ग्राम की गंदगी का पता चलता है। शोरूम संचालन द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहे स्वच्छता अभियान का माखोल उड़ाया जा रहा है। कचरे के ढेर के कारण गंदगी फेल रही है साथ ही गांव के आवारा पशु उक्त कचरे का प्लास्टिक खा रहे है। पास में ही पाटड़ी नदी और लोगो की कृषि भूमि है जहां इस कचरे के ढेर में से प्लास्टिक उड़कर नदी के पानी को दूषित कर रहे है और खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हो रहा है।

उक्त मामला ग्राम पंचायत के संज्ञान में भी है और गंदगी फैलाने वालों पर दंड की व्यवस्था भी है। लेकिन शोरूम संचालक के प्रभाव के चलते ग्राम पंचायत के जिम्मेदार उक्त कचरे के ढेर को अनदेखा कर निकल जाते है। शोरूम संचालक को समझदारी का परिचय देते हुए कचरा व्यवस्थित स्थान पर फेंककर ग्राम की सुंदरता और स्वच्छता अभियान में सहयोग करना चाहिए, न की अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गंदगी और कचरा फैलाना चाहिए।

# नपा और पीएचई विभाग के बीच फुटबाल बनी शहर की नल-जल योजना

## कलेक्टर मिश्रा ने करवाया मैच फिक्स, दोनों विभागों का आधा -आधा स्कोर

**माही की गूंज, झाबुआ।**

शहर के लिए 2017 में शुरू हुई 47 करोड़ की नल-जल योजना अब तक पूरी से धरातल पर नहीं उतर पाई है। इस योजना का लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है। शहर के कुछ क्षेत्रों में पाइप लाइन डलना अभी बाकी है। लगभग 2 करोड़ की लागत से डलने वाली उक्त पेयजल पाइप लाइन का कार्य फिलहाल शून्य पर है। शहर में कहीं भी अभी पाइप लाइन डालने का कर्य नहीं चल रहा है। हालांकि कि इस नवीन पेयजल योजना से शहर के कई हिस्सों में पेयजल आपुर्ति की जा रही है। तो कई हिस्सों में अब भी पुरानी व्यवस्थानुसार पेयजल वितरण हो रहा है। इस योजना के पूरी तरह से धरातल पर उतरने के पहले ही यह फुटबाल बन गई है। पेयजल वितरण को लेकर पीएचई और नगरपालिका के बीच एक -दूसरे पर गोल दागने का खेल चल रहा है।

शहर में पेयजल वितरण का कार्य पहले पूरी तरह से पीएचई विभाग के जिम्मे था। 50 साल पुरानी योजना से पीएचई विभाग अब तक शहर में जल वितरण करता आ रहा था, जो महज 15 हजार आबादी के हिसाब की थी। शहर की आबादी लगभग 50 हजार से अधिक होने के बावजूद भी पीएचई विभाग जैसे -तैसे कर शहर में जलआपुर्ति का कार्य करता रहा। 2017 में शहर को नई पयेजल योजना की सौगात मिली 2019 में इस नवीन योजना का काम पूरा हो गया। केवल शहर के कुछ हिस्से में पाइप लाइन डलना शेष रह गई है। इस नवीन पेयजल योजना से शहर में जलापुर्ति काम शुरू हुआ। मगर पूरे शहर को एकसाथ इसका लाभ नहीं मिला। शहर के आधे हिस्से में नवीन पेयजल योजना से नगरपालिका पानी सप्लाय करती तो आधे शहर में पीएचई पुरानी व्यवस्था से ही पेयजल आपुर्ति करती। यह क्रम लगभग डेढ़ साल से चल रहा था। अब जब कि नवीन पयेजल योजना लगभग पूर्ण हो चुकी है तो पीएचई विभाग भी इस झंझट से दूर होना चाहता है। मगर नगरपालिका में अब भी आत्मविश्वास नहीं है कि वह इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाएगी। बस इसी वजह से पीएचई और नगर पालिका के बीच यह योजना फुटबाल बनकर रह गई है।

पीएचई और नगरपालिका के बीच चल रहे इस मैच एक दूसरे पर गोल तो दागे जा रहे है लेकिन दर्शक दीर्घा में बैठी जनता को इसका खामियाजा जलसंकट से दो-चार होकर भुगतना पड़ रहा है। 6-7 दिनों में नगर में जल सप्लाय हो पा रहा है। लंबे समय से पेयजल योजना की वितरण प्रणाली को लेकर पीएचई और नगरपालिका के बीच यह खींचतान चल रही है। मगर अब तक कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आ रहा था। पेयजल योजना कभी पीएचई के पाले में तो कभी नगरपालिका के पाले फुटबाल की तरह पिटती नजर आ रही थी। निर्णय नहीं निकलने की दशा में मैच फिक्सिंग का दौर शुरू हुआ और कलेक्टर सोमेश मिश्रा मैच फिक्सर बने।

जून माह तक स्थिति यह थी कि, शहर के आधे हिस्से में पीएचई विभाग पुरानी पाइपलाइन के जरिए पेयजल वितरण करता था, तो आधे हिस्से में नगरपालिका नवीन योजना के माध्यम से पेयजल सप्लाय कर रही थी। जून माह में इन दो विभागों के बीच ऐसी रस्साकसी हुई की जनता को इसकी कीमत कई दिनों तक पेयजल संकट से जूझते हुए चुकानी पड़ी।

स्थिति 'दो पाटों में पिसने वाली बन गई।' जब पीएचई विभाग ने नगर पालिका के धरमपुरी डेम से पानी की मांग की तो नपा ने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि, हमारी ही पुर्ति नहीं हो रही है तो आपको पानी कहां से दें। जिस पर पीएचई विभाग ने अपने हिस्से की पेयजल वितरण व्यवस्था से हाथ खड़े कर दिए। वही नगरपालिका पेयजल व्यवस्था अपने हाथों में लेने से बचती दिखाई दी। नपा ने कई हवाले देते हुए असमर्थता जाहिर की, तो पीएचई ने साफ कह दिया कि, यह हमारा काम नहीं है। आखिरकार कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद दोनों विभागों में यह समझौता हुआ कि पीएचई विभाग और नगरपालिका विभाग एक माह तक एक साथ काम करें और नगरपालिका को पेयजल वितरण में आ रही समस्याओं को दूर करेंगे। हालांकि हस्तांतरण की औपचारिकताएं अब भी पूर्ण नहीं हो पाई है।

एक जुलाई से शहर की पेयजल व्यवस्था नगरपालिका के हाथों में थी, लेकिन शहर की जलप्रदाय व्यवस्था गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी है। पहले जब पीएचई विभाग और नगरपालिका आधे-आधे शहर में जल प्रदाय करते थे तो एक दिन छोड़कर तीसरे दिन शहरवासियों को जल प्रदाय हो पाता था। अब जब से यह व्यवस्था नगरपालिका के जिम्मे हुई है। तब से जलप्रदाय के दिनों का अंतराल बढ़कर पांचवें दिन हो गया है। पिछले दिनों जलप्रदाय में आई तकनीकि दिक्कत के कारण यह फांसला बढ़ता हुआ सीधे 7 दिनों पर पहुंच गया। इस स्थिति में मध्यम वर्गीय लोगों को खासा परेशान होना पड़ा। लोग मुश्किलों का सामना करते हुए हैंडपंपो या जल क्रय कर अपनी आपुर्ति कर रहे है। नगरपालिका शहर के हर उपभोक्ता को प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर पेयजल प्रदाय करने में फिलहाल तो नाकाम ही साबित हो रही है और आगे भी इसकी संभावनाएं लंबे समय तक कम ही नजर आ रही है। क्योंकि नपा की यह मजबूरी यह कि, वह नवीन योजना में बने डेम को पूरा नहीं भर पा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर डेम को पूरा भरा जाता है तो कई किसानों की जमीन डूब में आ रही है। जिसका मुआवजा अब तक किसानों को नहीं मिल पाया है। स्थिति यह है कि डेम की क्षमता 110 एमसीएफटी है, जिससे सिर्फ एक चौथाई यानि 35 एमसीएफटी ही भर पा रहे है। जब तक किसनों को मुआवजा नहीं मिल जाता डेम को पूरा भरने की स्थिति में नगरपालिका नजर नहीं आ रही है। किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए है। जिसकी फाइल पिछले कई वर्षो से भोपाली गलियारों में अटकी पड़ी है।

इधर पीएचई विभाग ने फिर से नगरपालिका की तरफ गोल दागने की कवायदें तेज कर दी। शहर में सुचारू रूप से पयेजल वितरण करने के लिए अब नगरपालिका ने पीएचई विभाग से उनके फिलटर प्लांट की मांग की। तो पीएचई विभाग ने भी 'जैसे को तैसा' कहावत चरितार्थ करते हुए। नगरपालिका को दो टुक में इंकान कर दिया। नगरपालिका और पीएचई के बीच चल रहे इस घमासान मैच का कोई नतीजा नहीं निकलते देख एक बार फिर कलेक्टर ने मैच फिक्सिंग की कवायदें तेज की।

दो विभागों के बीच चल रही इस जुतम पैजार ने शहरवासियों को मजबूर कर दिया और शिकायतें होना शुरू हुई। शिकायतों के बाद कलेक्टर मिश्रा नगरपालिका और पीएचई विभाग के अधिकारियों लेकर मैच फिक्सिंग करवाने मंगलवार शाम किशनपुरी के फिल्टर प्लांट पर पहुंचे। दोनो विभागों के बीत सुनने के बाद यह तय किया गया कि आने वाले मार्च माह तक पीएचई विभाग पहले की तरह अपनी व्यवस्थाएं जारी रखते हुए मोजीपाड़ा व दिलीपगेट स्थित पानी की टंकी में 5 लाख लीटर पानी रोज अपने पुराने प्लांट से भरेगा। शहर की बाकी 4 टंकियों में नगरपालिका नए प्लांट से पानी की व्यवस्था करेगी। यह वही व्यवस्था है जो पिछले जून माह के पहले तक चली आ रही थी। उसके बाद कलेक्टर ने नया प्लांट हैंडओवर होने के बाद नपा को यह जिम्मेदारी सौंपी थी।

कुल मिलाकर इस मैच फिक्सिंग में स्थितियां वही ढाक के तीन पात हो गई। मगर सवाल तो अब भी वही है कि क्या वाकई नगरपालिका इस कार्य को अकेले करने में सक्षम है? क्योंकि इस पेयजल योजना को अपने हाथ में लेने को लेकर नगरपालिका ने अब तक आत्मविश्वास नहीं दिखाया है। अगर नगरपालिका अपने आत्म विश्वास को नहीं बढ़ाती है तो यह मैच कभी खत्म नहीं होगा और परिणाम मैच फिक्सिंग के तौर पर ही सामने आते रहेंगे।


स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422